सम्पादकीय

पंजाब और हरियाणा में गहराता जल संकट

पंजाब और हरियाणा में धान की खेती भारत की खाद्य सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, परंतु जल पर अत्यधिक निर्भरता के कारण यह असंधारणीय होती जा रही है। धान की खेती के कारण भूजल का अत्यधिक दोहन होने से इस क्षेत्र में गंभीर जल संकट उत्पन्न हो गया है। हरियाणा में 88 जल इकाइयों को अत्यधिक दोहन वाली श्रेणी में रखा गया है। इस समस्या से निपटने के लिए कृषि और जल संसाधन दोनों की सुरक्षा के लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

पंजाब और हरियाणा में धान की खेती के लिए अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है, जिससे भूजल स्तर में भारी कमी आई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के 2023 में किए गए अध्ययन में पाया गया कि धान की खेती के लिए अत्यधिक जल दोहन के कारण पंजाब के 87% ब्लॉकों का अति दोहन किया गया। धान की खेती में प्रति किलो चावल के लिए लगभग 4,000-5,000 लीटर जल की खपत होती है, जिससे क्षेत्र के जल संसाधनों पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है। इसकी तुलना में बाजरे को प्रति किलो केवल 500 लीटर जल की आवश्यकता होती है, जो जल की आवश्यकताओं में भारी अंतर और धान की खेती की असंधारणीय प्रकृति को दर्शाता है। ट्यूबवेल के लिए दी जाने वाली मुफ्त बिजली ने भूजल के अनियंत्रित दोहन को बढ़ावा दिया है, जिससे यह संकट और भी बढ़ गया है। पंजाब के किसानों को वर्ष 2023-24 में बिजली, नहर के पानी और उर्वरक के लिए 38,973 रुपये प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी मिली, जिससे भूजल का निरंतर रूप से अतिदोहन हो रहा है। धान की खेती के कारण बढ़ता जल तनाव, जलवायु परिवर्तन के कारण और भी अधिक हो गया है, अनियमित वर्षा के कारण जलभृतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। पंजाब और हरियाणा के जल स्तर में तेजी से हो रही गिरावट से कृषि की दीर्घकालिक व्यवहार्यता को खतरा है।

धान की खेती एकल फसल प्रणाली को बढ़ावा देती है, जिससे जैव विविधता कम होती है और मृदा के पोषक तत्व कम होते हैं, जिससे कृषि संधारणीयता में कमी आती है। अध्ययनों के अनुसार फसल चक्रण से मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार होता है परंतु धान की खेती ऐसी विविधता को हतोत्साहित करती है। जल की अधिक माँग के कारण रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी बढ़ जाता है, जिससे मृदा की गुणवत्ता और भी खराब हो जाती है तथा जल स्रोत प्रदूषित हो जाते हैं। बाढ़ सिंचाई, धान की खेती में प्रयुक्त होने वाली एक प्रमुख विधि है, जिससे वाष्पीकरण और अपवाह के माध्यम से जल की बहुत बर्बादी होती है। निरंतर धान की खेती से मृदा लवणता बढ़ जाती है, जिससे कृषि भूमि की उत्पादकता कम हो जाती है और यह अन्य फसलों के लिए कम उपयुक्त हो जाती है। धान के खेत, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, विशेष रूप से मीथेन के उत्सर्जन में जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ाता है और दीर्घकालिक कृषि व्यवहार्यता को प्रभावित करता है। धान की खेती प्रति हेक्टेयर 5 टन कार्बोडीऑक्सीडे समतुल्य हानिकारक गैस उत्पन्न करती है, जो इसे कृषि उत्सर्जन में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनाती है।

घुटती सांसों से कम होती औसत आयु की चिन्ता

राजधानी समेत कई अन्य राज्यों में मेट्रो ट्रेन शुरू होने के बाद प्रदूषण में काफी कमी आई है। इस दिशा में हमें दीर्घकालीन नीतियों के बारे में सोचना होगा। हमारी कोशिश हो कि घनी आबादी के बीच चलायी जा रही औद्योगिक इकाइयों को शहरों से दूर स्थापित किया जाए। हमारे उद्यमियों को भी जिम्मेदार नागरिक के रूप में प्रदूषण नियंत्रण में योगदान देना चाहिए। नीति-नियंताओं को सोचना चाहिए कि प्रदूषण में अप्रत्याशित वृद्धि के बाद दिल्ली आदि महानगरों में चलाये जाने वाले ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रेप जैसी व्यवस्था को नियमित रूप से लागू क्यों नहीं किया जा सकता? ताजा कुछ अध्ययनों में बताया गया है कि बढ़ता प्रदूषण नवजात शिशुओं तथा बच्चों की जीवन प्रत्याशा पर बुरा प्रभाव डाल रहा है। ऐसे में हमें पराली के निस्तारण, औद्योगिक कचरे के नियमन तथा कार्बन उत्सर्जन करने वाले ईंधन पर रोक लगाने जैसे फौरी उपाय तुरंत करने चाहिए। ऐसे तमाम प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने की जरूरत है जो हमारे जीवन पर संकट पैदा कर रहे हैं।

ललित गर्ग।

वायु प्रदूषण का संकट भारत की राष्ट्रव्यापी समस्या है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की हाल ही में जारी रिपोर्ट इस चिन्ता को बढ़ाती है जिसमें कहा गया कि वायु प्रदूषण के चलते भारत में जीवन प्रत्याशा में गिरावट आ रही है। जिसमें फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाले पी.एम. 2.5 कण की बड़ी भूमिका है। रिपोर्ट बताती है कि वैश्विक मानकों से कहीं अधिक प्रदूषण भारत में लोगों की औसत आयु तीन से पांच वर्ष एवं दिल्ली में दस से बारह वर्ष कम कर रहा है। बहरहाल प्रदूषण के खिलाफ योजनाबद्ध ढंग से मुहिम छेड़ने की जरूरत है। अध्ययन कहता है कि देश की एक अरब से अधिक आबादी ऐसी जगहों पर रहती है जहां प्रदूषण डब्ल्यूएचओ के मानकों से कहीं अधिक है। दरअसल, देश के बड़े शहर आबादी के बोझ से त्रस्त हैं। बढ़ती आबादी के लिये रोजगार बढ़ाने व अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए जो औद्योगिक इकाइयां लगायी गई, उनकी भी प्रदूषण बढ़ाने में भूमिका रही है। डीजल-पेट्रोल के निजी वाहनों को बढ़ता काफिला, निर्माण कार्यों में लापरवाही, कचरे का निस्तारण न होना और जीवाश्म ईंधन ने प्रदूषण बढ़ाया है। यह बढता वायु प्रदूषण हमारी जीवन शैली से उपजे प्रदूषण की देन भी है।

यह निराशाजनक खबरों के बीच उत्साहवर्धक खबर यह भी है कि भारत में सूक्ष्म कणों से पैदा होने वाले जानलेवा प्रदूषण में गिरावट आई है। लेकिन अभी जीवन प्रत्याशा घटाने वाले प्रदूषण को लेकर जारी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट 'वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक-2024' बताती है कि भारत में साल 2021 की तुलना में 2022 के वायु प्रदूषण में 19.3 फीसदी की कमी आई है। हालांकि, यह उपलब्धि मौजूदा हालात में बहुत बड़ी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन यह बात उत्साहवर्धक है कि प्रत्येक भारतीय की जीवन प्रत्याशा में इक्यावन दिन की वृद्धि हुई है। हालांकि, हम अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं, लेकिन एक विश्वास जगा है कि युद्ध स्तर पर प्रयासों से भयावह प्रदूषण के खिलाफ किसी हद तक जंग जीती भी जा सकती है। लेकिन इसके साथ ही सूचकांक-2024 में यह चेताया भी है कि यदि भारत में डब्ल्यूएचओ के वार्षिक पीएम 2.5 के सांद्रता मानक के लक्ष्य पूरे नहीं होते तो भारतीयों की जीवन प्रत्याशा में करीब साढ़े तीन साल की कमी आने की आशंका पैदा हो सकती है। पीएम 2.5 श्वसन प्रणाली में गहराई तक प्रवेश कर सकता है और सांस संबंधी समस्याओं को जन्म देता है। यह स्वास्थ्य को एक बड़ा खतरा है और वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारक है। अध्ययन कहता है कि भारत के सबसे कम प्रदूषित शहर भी डब्ल्यूएचओ के निर्धारित मानकों से सात गुना अधिक प्रदूषित हैं। हम न भूलें कि देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की गिनती लगातार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानियों में होती रही है। दीवाली के बाद जब दिल्ली गहरे प्रदूषण के आगोश में होती है तो कोर्ट से लेकर सरकार तक अति सक्रियता दर्शाते हैं। लेकिन थोड़ी स्थिति सामान्य होने पर परिणाम वही 'ढाक के तीन पात'। कभी पेट्रोल-डीजल के नये मानक तय होते हैं तो कभी जीवाश्म ईंधन पर रोक लगती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वर्ष 2019 में प्रदूषण कम करने को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम देश के सौ से अधिक शहरों में शुरू किया था। चार साल बाद पता चला कि किसी भी शहर ने अपने लक्ष्य को पूरा नहीं किया। विकासशील देश पहले ही निर्धारित वायु गुणवत्ता के मानक पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वहीं डब्ल्यूएचओ ने मानकों को और कठोर बना दिया है। सभी सरकारों व नागरिकों का दायित्व बनता है कि अपने-अपने स्तर पर प्रदूषण को कम करने वाली जीवन शैली अपनाएं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि पूरी दुनिया में सत्तर लाख मौतें हर साल प्रदूषित वायु के चलते हो रही हैं। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक के अनुसार हवा में पीएम 2.5 और पीएम 10 के वार्षिक स्तर की सुरक्षित सीमा क्रमशः चालीस माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और साठ माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर होनी चाहिए। हालांकि, ये मानक विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानकों से कहीं ज्यादा हैं। दरअसल, हमारे नीति-नियंता प्रदूषण कम करने के लिये नागरिकों को जागरूक करने में भी विफल रहे हैं। हमारी सुख-सुविधा की लालसा एवं भौतिकतावादी जीवनशैली की चमक ने भी वायु प्रदूषण बढ़ाया है। अब चाहे गाहे-बगाहे होने वाली आतिशबाजी हो, प्रतिबंध के बावजूद पराली जलाना हो, या फिर सार्वजनिक परिवहन सेवा से परहेज हो, तमाम कारण प्रदूषण बढ़ाने वाले हैं। कल्पना कीजिए बच्चों और दमा, एलर्जी व अन्य सांस के रोगों से जूझने वाले लोगों पर इस प्रदूषण का कितना घातक असर होगा? रिपोर्ट में उल्लेखित प्रदूषण में आई गिरावट की वजह अनुकूल मौसम संबंधी परिस्थितियां बतायी गई हैं। हालांकि, हकीकत यह भी है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिये चलायी जा रही कई योजनाओं के सकारात्मक परिणामों का भी इसमें योगदान रहा है। खासकर भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जिन शहरों को शामिल किया गया था, वहां भी पीएम-2.5 सांद्रता में गिरावट देखी गई है। वहीं स्वच्छ ईंधन कार्यक्रम का सकारात्मक प्रभाव प्रदूषण नियंत्रण पर नजर आया है। इससे भारत के रिहाइशी इलाकों में कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिली है। ऐसी योजनाओं को पूरे देश में लागू करने का सुझाव भी दिया गया है। बहरहाल, हमें वर्ष 2022 के उत्साहजनक परिणामों के सामने आने के बाद व्यापक लक्ष्यों के प्रति उदासीन नहीं होना है। यह एक लंबी लड़ाई है और इसमें सरकार व समाज की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। हमें इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि सरकारों के भरोसे ही लगातार गहराते पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। निश्चित ही वायु प्रदूषण से उत्पन्न दमघोटू माहौल का संकट जीवन का संकट बनता जा रहा हैं। वायु प्रदूषण का ऐसा विकराल जाल है जिसमें मनुष्य सहित सारे जीव-जंतु फंसकर छटपटा रहे हैं, जीवन सांसों पर छाये संकट से जूझ रहे हैं। यह समस्या साल-दर-साल गंभीर होती जा रही है। सरकारें अनेक लुभावने तर्क एवं तथ्य देकर समस्या को कमतर दिखाने की कोशिशें करती है। लेकिन हकीकत यही है कि लोगों का दम घुट रहा है। अगर वे सचमुच इससे पार पाने को लेकर गंभीर हैं, तो वह व्यावहारिक धरातल पर दिखना चाहिए। प्रश्न है कि पिछले कुछ सालों से लगातार इस महासंकट से जूझ रहे राष्ट्र को कोई समाधान की रोशनी क्यों नहीं मिलती? वास्तव में यह विभिन्न राज्य सरकारों का गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, जिसने सबको जहरीले वायुमंडल में रहने को विवश किया है। इस विषम एवं ज्वलंत समस्या से मुक्ति के लिये हर राजनीतिक दल एवं सरकारों को संवेदनशील एवं अन्तर्दृष्टि-सम्पन्न बनना होगा। प्रदूषण से ठीक उसी प्रकार लड़ना होगा जैसे एक नन्हा-सा दीपक गहन अंधेरे से लड़ता है। छोटी औकात, पर अंधेरे को पास नहीं आने देता। क्षण-क्षण अग्नि-परीक्षा देता है। पर हां! अग्नि परीक्षा से कोई अपने शरीर पर फूस लपेट कर नहीं निकल सकता।

आज का राशिफल

हमारे अनुभवी ज्योतिषियों की टीम के अनुसार आप कई विविध लक्ष्यों को पूरा करेंगे। क्या आप यह जानना चाहते है कि आपके जीवन के ऐसे कौनसे क्षेत्र है, जहां आपके सितारे बुलंद होंगे और दूसरी तरफ, आपको किन बातों से सावधान रहना चाहिए। हम न सिर्फ तुम्हारे काम में और जटिल मुद्दों को सुलझाने तथा सकारात्मक ऊर्जा को मजबूत करेंगे, बल्कि पारस्परिक संबंधों में भी, जहां यह सकारात्मकता हमें संवाद और बातचीत में लाभ प्रदान करेगा

मेष

आपके व्यवहार से आज किसी के मन को ठेस पहुंच सकती है। व्यवहार को भी संयमित रखें। वैचारिक नकारात्मकता से दूर रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मन ग्लानि से भरा रहेगा। विद्यार्थियों को विद्याप्राप्ति में अवरोध उत्पन्न हो सकता है।

वृष

हर काम में यश प्राप्त होने का योग बन रहा है। हालांकि खर्च की मात्रा अधिक रहने की आशंका है, इसका ख्याल रखें। आज रचनात्मकता और कला संबंधी प्रवृत्तियों के लिए दिन श्रेष्ठ है। अपनी रचनात्मकता से सभी को प्रभावित कर सकते हैं।

मिथुन

आज आपको क्रोध पर संयम बरतने की सलाह दी जाती है। अत्यधिक क्रोध के कारण आपके काम और संबंधों के बिगड़ने की आशंका है। मानसिक रूप से व्यग्रता और बेचैनी के कारण किसी काम में आपका मन नहीं लगेगा।

कर्क

किसी धार्मिक स्थल या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। शारीरिक रूप से अस्वस्थ रहने तथा कार्य सफलता प्राप्त करने में विलंब होने से आपको निराशा हो सकती है। आज किसी नए काम का आरंभ न करें। मानसिक रूप से भी प्रसन्नता बनी रहेगी।

सिंह

माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। स्थायी संपत्ति के कामों में सावधानी बरतें। आज का दिन आनंद में गुजरेगा। विरोधियों के समक्ष विजय का स्वाद प्राप्त कर सकेंगे। प्रत्येक काम में सफलता मिलेगी। स्वजनों के साथ भी आज भेंट होगी।

कन्या

आज आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज के दिन निर्धारित किए हुए कार्य पूरे होंगे। भाग्य आपका साथ देगा। शारीरिक तथा मानसिक स्वस्थता आपको प्रसन्न रखेगी। किसी यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। लोगों के साथ अनबन हो सकती है।

तुला

आज कार्यभार की अधिकता के कारण शिथिलता रहेगी। योग, ध्यान और आध्यात्मिकता का सहारा लेकर मन की शांति पर ध्यान दें। आज का दिन आनंद-प्रमोद में गुजरेग। शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुशी का अनुभव करेंगे।

वृश्चिक

आज का दिन प्रतिकूलताओं से भरा रहने के संकेत हैं। शारीरिक ताजगी का आज अभाव रहेगा और मानसिक रूप से भी चिंता बनी रहेगी। पत्नी के साथ कलह का प्रसंग बन सकता है, जिससे मन विचलित रहेगा।

धनु

मित्रों और परिजनों के साथ प्रवास या पर्यटन स्थल पर घूमने-फिरने का आनंद उठा सकेंगे। स्वादिष्ट भोजन का स्वाद ले सकेंगे। आज आपको वाहन सुख भी मिलेगा। आपके मान-सम्मान और लोकप्रियता में वृद्धि होने के संकेत हैं।

मकर

व्यवसाय में आज का दिन लाभदायी रहने की संभावना है। कार्यालय में सहकर्मियों का सहयोग भी प्राप्त होगा। आज के दिन मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थता का अनुभव होगा। वैचारिक नकारात्मकता से दूर रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कुंभ

मानसिक रूप से भी प्रसन्नता बनी रहेगी। आज आपको धार्मिक प्रवास से मानसिक खुशी मिलेगी। संबंधों में हो रही भावना आपके मन को द्रवित कर देगी। परिवार में क्लेशमुक्त वातावरण न हो, इसके लिए वाणी पर संयम रखें।

मीन

विद्यार्थी अभ्यास में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। स्नेहीजनों और मित्रों के साथ मुलाकात होगी, जिससे मन बेहद खुश रहेगा। शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहने की उम्मीद है। मानसिक एकाग्रता के लिए अपने गुस्से पर संयम रखें। आपको विरोधियों पर विजय मिलेगी।

शख्सियत

जज्बे का अपना अलग रंग होता है ये दिखता नहीं लेकिन महसूस होता है। जीवन में कुछ कामों में दिमाग नहीं बल्कि जज्बा चाहिए होता है

नमस्कार दोस्तों हमारी आज की शख्सियत कॉलम के स्टार हैं राजस्थान पुलिस में अपनी सेवाए देने वाले सेवानिवृत पुलिस निरीक्षक दामोदर गुर्जर। दामोदर सिंह गुर्जर का जन्म डीग तहसील में सन 1962 को हुआ इनके पिता शोभाराम जी भी राजस्थान पुलिस के जांबाज इंस्पेक्टर रहे थे। उन्हें उन्हीं के साथ रहकर इन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूर्ण करने के पश्चात पुलिस में बतौर कांस्टेबल के रूप में भर्ती ली। कॉस्टेबल रह कर इन्होंने जिला एसपी द्वारा चलाए गए अभियान में नामी गरामी बदमाशों व फरार मुजरिमों को पकड़ा। जिला अजमेर में इनकी पहली पोस्टिंग हुई उसके बाद में कांस्टेबल से हैडकॉंस्टेबल का सफर उसके बाद हैडकॉंस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक का सफर उसके बाद ये पुलिस उपनिरीक्षक बने तो कई जिलों में ये एसएचओ भी रहे। उसके बाद जब ये पुलिस इंस्पेक्टर बने तो भरतपुर,करौली व धौलपुर में अनेक नामी बदमाशों को पकड़ा व उनके सही ठिकाने पहुँचाया। अलवर व दौसा में कार्यरत भी रहे और इनका अंतिम पद स्थापथ यातायात पुलिस निरीक्षक अलवर के तौर पर रहा। यातयात पुलिस में रह कर भी इन्होंने डिप्टी एसपी ट्रैफिक हरीराम मीणा के साथ मिलकर अनेकों अभियान चलाए। करौली में इन्होंने डाकूओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन दस्यु में बेहद शानदार भूमिका निभाते हुए राजस्थान पुलिस के जज्बे व इकबाल को बनाए रखा। सेवानिवृत के बाद अब अपना समय परिवार के लिए दे रहे हैं। दैनिक बढ़ता राजस्थान टीम इनके उज्ज्वल भविष्य व दीर्घायु जीवन की कामना करती है।

दामोदर सिंह गुर्जर
(पुलिस निरीक्षक सेवानिवृत)

जय हिन्द
रूपक शर्मा

आज का इतिहास

11 सितंबर की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

- ऐलॅक्सैण्डर हैमिलटन अमेरिका के प्रथम वित्त सचिव 1789 में नियुक्त।
- आज ही के दिन वर्ष 1803 को द्वितीय आंग्ल-मराठा युद्ध के अंतर्गत दिल्ली लड़ाई की शुरुआत की गयी थी।
- प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन 1896 को शिकागो, अमेरिका में आयोजित हुआ।
- सितम्बर वर्ष 1906 को महात्मा गाँधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन आरंभ किया।
- आस्ट्रेलिया के मेलबर्न में 1922 को सचित्र दैनिक समाचार पत्र द सन न्यूज पेक्टोरियल का आरंभ हुआ।
- द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 में इराक और सऊदी अरब ने एक साथ मिलकर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी।
- अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का 1941 में निर्माण शुरू हुआ।
- इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली फ्लोरेंस चैडविक 1951 में पहली महिला बनी। उन्हें इंग्लैंड से फ्रांस पहुंचने में 16 घंटे और 19 मिनट लगे थे।
- विश्व वन्यजीव कोष का स्थापना 1961 में हुई।
- मशहूर इंग्लिश रॉक बैंड 'दि बीटल्स' ने 1962 में अपने पहले एकल हिट एलबम 'लव मी डू' के गाने रिकार्ड किए थे।
- भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान 1965 में भारतीय सेना ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए दक्षिण पूर्वी लाहौर के निकट बुर्की शहर पर कब्जा कर लिया था।
- एयर फ्रांस का विमान संख्या 1611 नाइस के निकट 1968 को दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 89 यात्रियों और चालक दल के छह सदस्यों की मौत।
- मिस्र में 1971 में संविधान को अंगीकार किया गया।
- चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर अलांदे का 1973 में सैन्य तख्तापलट हुआ।
- शिकागो में 1893 को विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कट्टरता, सहिष्णुता और सभी धर्मों में निहित सच्चाई पर ऐतिहासिक भाषण दिया।
- राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में 1996 को पहली बार एक महिला अध्यक्ष निर्वाचित।
- अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2001 को हुए आतंकी हमले में 6 हजार से अधिक लोग मारे गए।
- आज ही के दिन स्वीडन की विदेश मंत्री एना लिंध की 2003 में एक अस्पताल में मौत हुई थी।
- चीन के विरोध के बावजूद 2003 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा से अमेरिकी राषट्रपति जॉर्ज बुश मिले।
- गाजा पट्टी में 38 सालों से जारी सैन्य शासन समाप्त करने की घोषणा 2005 में की।
- पेस और डेम की जोड़ी ने 2006 में अमेरिकी ओपन का युगल खिताब जीता।
- भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश पी.एन. भगवती 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति में चौथी बार पुनर्निर्वाचित।
- प्रख्यात बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने 2006 में भारतीय नागरिकता की मांग की।
- स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर को 2006 में लगातार तीसरी बार अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता।
- अमेरिकी अंतरिक्ष यान 2006 में अटलांटिस अंतरिक्ष के साथ जुड़ा।
- येरूशलम से सटे डेविड शहर में 2007 को लगभग 2000 साल पुरानी सुरंग का पता लगा।
- रक्षा वैज्ञानिकों ने 2011 में बनायी 'ल्यूकोडर्मा' की अचूक हर्बल औषधि। इस हर्बल द्रव और लगाने के लिए मलहम रूप में होगी।
- इस दवा के व्यावसायिक उत्पादन और मार्केटिंग के लिए डीआरडीओ ने देश की एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी से करार किया है, जो तकनीकि हस्तांतरण से इसका उत्पादन शुरू करने जा रही है।

विशेष आलेख

युवा चिंतन : सफलता-असफलता जीवन के दो पहलू, श्रम-संयम का दामन ना छोड़े

संजीव ठाकुर

आकस्मिक बड़ी सफलता एवं भारी असफलता आदमी पचा नहीं पाता मानसिक संतुलन बिगड़ने की संभावना बढ़ जाती है। सफलता तो फिर भी व्यक्ति खुशी से आत्मसात कर लेता है पर असफलता को झेलने के लिए आत्मविश्वास,मनोबल की परम आवश्यकता होती है। असफलता ऐसा स्वाद है जिसे हर व्यक्ति ने जीवन में कभी ना कभी जरूर चखा होगा। असफल होने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। महापुरुषों ने कहा है कि असफलता यह दर्शाती है कि आपने प्रयास पूरे मन से नहीं किया है अत: असफलता के बाद सफलता के लक्ष्य को निर्धारित कर पूर्ण मनोयोग से कर्म की वेदी पर अपना शीश नवाना चाहिए। जीवन में असफलता किसी लक्ष्य को स्थापित करने का ही परिणाम है, इसीलिए इसे बड़े ही सौजन्यता से, सहज तरीके से आत्मसात करना चाहिए। सकारात्मक तरीके से आत्मविश्वास के साथ स्वीकार की गई असफलता मनुष्य को बड़े लक्ष्य की ओर प्रयास करने के लिए संकेत देती है। बिना असफलता के सफलता कोई भी स्वाद नहीं देती है। असफलता के बाद ही सफलता के के लिए किए गए प्रयासों का महत्व मनुष्य को अपने जीवन में पता लगता है। शायर फैज अहमद फैज ने कहा है

दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है,
लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।

असफलता सफलता की पहली सीढ़ी है और यह सामान्य मानवीय कृत्य भी है। असफल होने के कारणों का पता लगाकर सफलता के लिए प्रयास हमेशा हमें दोगुना कर देना चाहिए। यह भी जरूरी नहीं है कि एक बार सफल होने के बाद मनुष्य सदैव सफल ही होता रहे इसके लिए मनुष्य को लगातार चिंतनशील, आत्म विश्वासी, साहसी और सतर्क होना पड़ेगा। सफल होने के लिए हमें हमेशा हुनरवान होना होगा जिससे इसी हुनर से हमें सफलता का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। यह सर्वविदित सच्चाई है कि हमें सफलता के लिये साहस और हुनर का उपयोग कर सदैव अग्रसर होते रहना होगा। सफलता एक लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव सफलता की सीढ़ी चढ़कर हमें वहां पहुंचने की आवश्यकता है। आत्मविश्वास का अर्थ शक्ति और ऊर्जा तो है और यह संपूर्ण रूप से हमारे प्रयासों हमारे संकल्प और साहस से जुड़ा हुआ प्रतिफल भी है।

आज भारत विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है। हमारे देश के लाखों, करोड़ों युवाओं का जीवन लक्ष्य हीन है वे बहुत सारी इच्छाएं और महत्वकांक्षी रखते तो हैं पर उसके पीछे कड़ी मेहनत पक्का इरादा नहीं रखने की भूल कर देते हैं और यही कारण है कि वे जीवन में इधर उधर भटक कर अत्यंत निराश होकर अपने जीवन को नशे और अन्य निराशाजनक मार्ग को अपना लेते हैं। प्रयास तथा कठिन परिश्रम की कमी ही युवा वर्ग की भटकाव की स्थिति की परिणति है। आज का युवा बिना सुनियोजित प्रयास के लक्ष्य की प्राप्ति की आकांक्षा रखने लगे हैं और असफल होने के बाद उसका मूल्यांकन ना

कर असफल होकर किसी अन्य मार्ग को चुनने के लिए बाध्य हो जाते युवाओं की यह मानसिक स्थिति बड़ी आया हुआ है जो समाज के लिए निर्णायक साबित होती है और एक बड़ा युवा वर्ग गलत मार्ग की ओर प्रशस्त हो जाता है। ऐसे में युवाओं का जीवन बहुत ही कष्टदायक हो सकता है। युवा वर्ग को चाहिए कि लक्ष्य निर्धारित कर उसके लिए निरंतर कोशिश है और निरंतर श्रम करना चाहिए इसके बाद भी यदि असफलता मिलती है तो सम्यक मूल्यांकन कर असफलता के कारणों को दूर कर दुगनी रफ्तार से मेहनत कर उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज युवा आगे बढ़कर देश का जिम्मेदार नागरिक बनेगा ऐसे में युवाओं को सदैव लक्ष्य प्राप्ति और सफलता प्राप्ति के लिए निरंतर कठिन श्रम प्रयास संकल्प और अपनी जीवनी को नियमित रखना होगा जिससे घर, समाज और राष्ट्र की उन्नति भी होगी। उल्लेखनीय है की असफलता से ही सफलता की तमाम शिक्षा हमें प्राप्त होती है। विवेकानंद जी ने कहा है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे ही भीतर ही है यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहते हैं कि अंधेरा है। मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास ही ऐसा गुण है जिससे हम संकल्पित होकर बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर जीवन में सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री, नरेंद्र मोदी और सबसे बड़े सफलता के और आत्मविश्वास के उदाहरण महात्मा गांधी ही हैं जिन्होंने आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से देश को आजादी दिलाने का महान कार्य किया है। फिर ऐसा क्या है कि देश के युवा वर्ग की बड़ी जनसंख्या हाथ में हाथ धरे सफलता का बैठे-बैठे इंतजार करना चाहती है। देश के नौजवानों को हमारे सफल महापुरुषों से शिक्षा लेकर सफलता के लिए अनंत तक आत्मविश्वास के साथ निरंतर श्रम करना चाहिए जिससे न सिर्फ उनका भला हो बल्कि पूरे समाज और पूरे देश का भला हो सके और देश पूरे विश्व में सीना तान कर अपने आसपास और सफलता की गाथा सुना सके। यह देखा गया है कि मानव अहंकार को ही आत्मविश्वास समझने की भूल कर देते हैं किंतु आत्मविश्वास घमंड और अहंकार में बहुत बड़ा फर्क है। आत्मविश्वास अहंकार विहीन विनम्रता के साथ परिश्रम और संयम संकल्प लेकर सफलता के लक्ष्य की ओर पदार्पण ही है। फल स्वरुप अहंकार को त्याग कर संपूर्ण विश्वास को लेकर देश हित में सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक श्रीमती कमलेश विजयवर्गीय द्वारा बढ़ता राजस्थान प्रिंटिंग प्रेस,इमीपपुरा रोड खण्डवा,निवाई टोंक (राज.) से मुद्रित एवं 185/ 116 "प्रतीक्षा" सेक्टर-18, प्रताप नगर सांगानेर, जयपुर से प्रकाशित, संपादक-तनुजा पठान"। प्रधान संपादक-राम बिलास विजयवर्गीय मो. 9414242258, 9214048888,जयपुर फोन नं.0141-2796794,795 टोंक कार्यालय-बाईपास निवाई, टोंक फोन नं.01432-244881 निवाई 01438-222201,202,203 अलवर कार्यालय-मेहताब सिंह का नोहरा,अलवर मो. 7733000123,कोटा कार्यालय-छावनी मेन रोड,कोटा मो.9414823448 । ई मेल-badhatarajasthan@yahoo.com *पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार

कल्पमेधा

तर्क आपको एक स्थान अ से दूसरे स्थान ब तक ले जाएगा, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है।

- अल्बर्ट आइंस्टाइन

विरोध बनाम दायित्व

कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या की घटना के खिलाफ चिकित्सकों के आंदोलन का आधार बिल्कुल उचित है। यह भी कहा जा सकता है कि इस मुद्दे पर उभरे जनाक्रोश की वजह से ही सरकारी तंत्र के भीतर कानूनी कार्रवाई को लेकर सजगता देखी जा रही है। मामले की जांच सीबीआइ भी कर रही है और इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट भी जरूरी सवाल उठा रहा है, जिसका जवाब देना पश्चिम बंगाल सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। मगर इसका एक पहलू यह भी है कि राज्य में इस घटना के खिलाफ चिकित्सकों का जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, उसके एक महीने से ज्यादा समय से जारी रहने की वजह से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा बुरी तरह बाधित हुई है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान सोमवार को पश्चिम बंगाल सरकार ने बताया कि चिकित्सकों के विरोध प्रदर्शन की वजह से तेईस मरीजों की जान चली गई।

चिकित्सकों की हड़ताल और उनके आक्रोश के औचित्य को समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। मगर अफसोस की बात यह है कि कोलकाता में हुई त्रासद वारदात में आरोपी सहित संदेह के घेरे में आए अन्य जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई के मामले में अनिवार्य सजगता नहीं दिखाई गई। यही वजह है कि समूचे देश में इस घटना के खिलाफ आक्रोश पैदा हुआ। इसमें देश के अलग-अलग हिस्से में उभरा चिकित्सकों का आंदोलन भी है। यों कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए जब चिकित्सकों से काम पर लौटने को कहा था, तब दिल्ली के कुछ अस्पतालों में डॉक्टरों ने ड्यूटी पर वापस आने की बात कही, मगर पश्चिम बंगाल में चिकित्सकों का आंदोलन अपनी मांगों पर डटा रहा। अब एक बार फिर अस्पतालों में सेवा बाधित होने और उसकी वजह से मरीजों के सामने पैदा होने वाले जोखिम की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चिकित्सकों को ड्यूटी पर लौटने का निर्देश देते हुए कहा कि कामकाज शुरू करने पर उनके खिलाफ कोई विपरीत कार्रवाई नहीं की जाएगी।

यह छिपा नहीं है कि अगर किसी भी वजह से सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सेवा ठप होती है तो इसका सीधा असर वहां आने वाले मरीजों की सेहत पर पड़ता है, जो आमतौर पर गरीब तबकों से आते हैं। ऐसे मरीजों और उनके परिजनों के सामने महंगे निजी अस्पतालों या डाक्टरों के क्लीनिक में जाकर इलाज का खर्च उठाने की सामर्थ्य नहीं होती। वे इलाज के लिए आमतौर पर सरकारी अस्पतालों पर निर्भर होते हैं। ऐसे में चिकित्सकों के ड्यूटी पर नहीं लौटने का खमियाजा उन्हें ही उठाना पड़ रहा है। इस क्रम में राज्य सरकार की ओर से अदालत में बताए गए तेईस मरीजों की मौत के आंकड़े सही हैं, तो यह चिंताजनक है। समय पर चिकित्सा या अस्पतालों में कामकाज को वैसे भी अनिवार्य सेवाओं के तहत देखा जाता रहा है। प्रशिक्षु चिकित्सक के बलात्कार और उसकी हत्या से सभी लोग दुखी और आक्रोशित हैं। मगर जरूरत इस बात की भी है कि सरकारी अस्पतालों के भरोसे जीवन बचाने की उम्मीद पर टिके मरीजों की मुश्किल के मसले पर भी प्रदर्शनकारी चिकित्सक अपने दायित्व पर विचार करें। इसमें दो राय नहीं कि घटना की जांच, अपराध के साबित होने और दोषी को अधिकतम सख्त सजा मिलने के संदर्भ में कानूनी कार्रवाई के किसी भी पहलू पर अगर सरकार अब कोई ढीला रवैया अख्तियार करती है, तो उसे कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए।

युद्ध का दंश

इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध में आम नागरिकों पर हमले और उनकी हत्या के औचित्य पर शुरू से सवाल उठते रहे हैं। मगर इजराइल ने शायद ही कभी इस बात की फिक्र की। अब एक बार फिर गाजा पट्टी में इजराइल के ताजा हमले में कम से कम उन्नीस लोगों की जान चली गई। खबरों के मुताबिक, इजराइल ने खान यूनिस शहर के जिस इलाके में यह हमला किया, वहां युद्ध में विस्थापित हुए फिलिस्तीनी लोगों ने शरण ली हुई है। इजराइली सेना ने इसे खुद मानवीय क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है। इसके बावजूद वहां इस स्तर का हमला करना समझ से परे है। हालांकि, इजराइल का तर्क है कि यह हमला हमास के शीर्ष लड़ाकों को निशाना बनाने के इरादे से किया गया, जो वहां स्थित कमान एवं नियंत्रण केंद्र के भीतर काम कर रहे थे। अगर उसकी आशंका सही हो तो भी क्या बड़ी तादाद में आम लोगों की हत्या को उचित ठहराया जा सकता है? दुनिया भर में सशस्त्र संघर्षों या युद्ध की स्थिति में आम लोगों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कायदे-कानून की नियमावली तैयार की गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी युद्धकाल के दौरान मानव बस्तियों, शिक्षा संस्थानों, अस्पतालों और आपदा राहत व मानव सहायता केंद्रों या शरणस्थलों पर हमले को नियमों के गंभीर उल्लंघन की सूची में शामिल किया है।

विडंबना यह है कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध हो या फिर रूस और यूक्रेन के बीच, आम नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े कानूनों पर अमल जरूरी नहीं समझा जा रहा। गाजा पट्टी में इजराइल के हमलों में आम लोगों के हताहत होने की खबरें पहले भी कई बार आती रही हैं। हमास के लड़ाकों ने जब इजराइल की सीमा में घुसपैठ कर जनसंहार की वारदात को अंजाम देकर इस युद्ध की शुरुआत की थी तब इजराइल ने इसे अंतरराष्ट्रीय आम नागरिक सुरक्षा नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया था। मगर अब इजराइल की ओर से गाजा पट्टी में हो रहे हमलों में जो तस्वीर सामने आ रही है, उसे कैसे उससे अलग रूप में देखा जाएगा! सवाल है कि अगर युद्ध के दौरान आम नागरिकों की सुरक्षा का खयाल नहीं रखा जाता है तब फिर अंतरराष्ट्रीय कायदे-कानूनों का क्या महत्त्व है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत तमाम देशों को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

कुप्रबंधन से बिगड़ती स्थितियां

इस वर्ष दिल्ली में जल निकासी के लिए सोलह सौ करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। बावजूद इसके, दिल्ली में कम से कम पचास जगहों पर विकट जलभराव जैसे हालात बन गए।

अखिलेश आर्येंदु

शहरों में बरसाती पानी की बेहतर निकासी न होने से अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। दिल्ली में यह समस्या कहीं ज्यादा गंभीर है। सरकार हर वर्ष जल निकासी के बेहतर उपाय करने का भरोसा दिलाती है, मगर वह जमीन पर उतरता नहीं दिखता। इस वर्ष फिर दिल्ली सरकार ने जलभराव और बाढ़ जैसे हालात से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए दीर्घकालीन योजनाएं बनाई हैं। इनमें जल निकासी व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ाना, अधिकारियों के आपसी टकराव को दूर करना, जलभराव के लिए स्थायी समाधान खोजना, अतिक्रमण हटाना और निर्माण, तोड़फोड़ और डेयरी कचरे का प्रभावी प्रबंधन करना शामिल है। इन कोशिशों से यह उम्मीद बनी है कि मौजूदा बुनियादी ढांचे में सुधार और विभिन्न एजंसियों के बीच समन्वय करके जलभराव को रोक पाना संभव हो पाएगा।

इस वर्ष दिल्ली में जल निकासी के लिए सोलह सौ करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। बावजूद इसके, दिल्ली में कम से कम पचास जगहों पर विकट जलभराव जैसे हालात बन गए। दरअसल, दिल्ली में कुप्रबंधन महज बारिश के पानी को लेकर नहीं है। सड़कों पर अतिक्रमण, बेतरतीब ढंग से इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकना और मनमाने ढंग से कहीं भी झुग्गी बना कर रहने लग जाना जैसे दिल्ली की पहचान बन गई है। जनवरी में हुए स्वच्छता सर्वेक्षण में 446 शहरों में दिल्ली को नब्बेवां स्थान मिलना भी इस बात की तस्दीक करता है कि दिल्ली में कई स्तरों पर कुप्रबंधन है, जिसका मुकम्मल समाधान निकालना जरूरी है।

बरसात दिल्ली जैसे महानगर के लिए आफत बन जाए तो, इसे किसकी नाकामी माना जाएगा? घरों, दफ्तरों और राजकीय भवनों में पानी घुसना दिल्ली जैसे शहर की सेहत के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। अब जब भारत को दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनने की बात कही जा रही हो, तो कुप्रबंधन से उपजी समस्याएं विश्व मीडिया का ध्यान खींचती ही हैं। सवाल है कि आखिर कब तक राजधानी में जलजमाव की समस्या हल होगी?

दरअसल, दिल्ली की अनियोजित बसावट के कारण यातायात और जाम की समस्या, सड़कों पर घंटों पानी भरे रहना, निचली जगहों और पुलों के नीचे पानी भर जाने जैसी समस्याएं अधिक हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग बरसात का इंतजार करते हैं और बरसात होने पर जब पानी घर के अंदर घुसने लगता और राहत आफत में तब्दील हो जाती है, तो दिल्ली के विकास पर सवालिया निशान लगता ही है। दिल्ली की यातायात, जल निकासी, नाले और नालियों की सफाई और कचरा प्रबंधन की समस्या का हल न निकाल पाने की वजह तलाशने की चाहे जितनी कोशिश की जाए, वह परवान नहीं चढ़ सकती है, जब तक इन विभागों से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों में समस्या की गहराई और उससे जुड़ी संवेदना नहीं जागती।

भारत के तमाम महानगरों में यातायात, वर्षा जल निकासी और कचरा निपटान की समस्या एक जैसी है। डब्लूआरआइ इंडिया की एक शोध परियोजना के शुरुआती निष्कर्षों से मालूम होता है कि भारत के दस सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों (दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, सूरत और बंगलुरु) में 2000-2015 (शहर के केंद्र के दस किमी के भीतर) के बीच हुए नए नगरीय विकास कार्यों के तहत बनी 35 फीसद इमारतों का निर्माण (428 वर्ग किमी) भूजल पुनर्भरण की अधिक या अत्यधिक संभावना वाले निचले इलाकों में हुआ है। ये सभी शहर कई वर्षों से बाढ़ या डूब जैसी समस्या से जूझते नजर आते हैं।

> **भारत के तमाम महानगरों में यातायात, वर्षा जल निकासी और कचरा निपटान की समस्या एक जैसी है। डब्लूआरआइ इंडिया की एक शोध परियोजना के शुरुआती निष्कर्षों के मुताबिक, भारत के दस सबसे ज्यादा आबादी वाले शहरों में 2000-2015 (शहर के केंद्र के दस किमी के भीतर) के बीच हुए नए नगरीय विकास कार्यों के तहत बनी 35 फीसद इमारतों का निर्माण (428 वर्ग किमी) भूजल पुनर्भरण की अधिक या अत्यधिक संभावना वाले निचले इलाकों में हुआ है। ये सभी शहर कई वर्षों से बाढ़ या डूब जैसी समस्या से जूझते नजर आते हैं।**

इस साल गर्मी ने पिछले सारे रेकार्ड तोड़ दिए। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इसकी वजह जलवायु परिवर्तन है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बरसात और गर्मी के मिजाज में बदलाव हुआ है। पिछले कई वर्षों से यह देखने में आ रहा है कि एक महीने या पूरे ऋतु में जितनी औसत बरसात होनी थी वह एक या कुछ दिनों में ही हो गई। जैसे दिल्ली में 28 जून को एक ही दिन में 228.1 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले 24 जून, 1936 को 235.5 मिलीमीटर बारिश हुई थी। जाहिर है, 88 साल पहले दिल्ली का रूप आज जैसा नहीं था। न इतने लोग थे और न इतनी कालोनियां थीं। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 28 जून को हुई बारिश में दिल्ली में पचास जगहों पर विकट जलभराव के हालात देखे गए। जलभराव से निपटने के लिए दिन भर संबंधित विभागों की टीमें लगी रहीं, लेकिन शाम तक भी यातायात सामान्य नहीं हो पाया। पिछले साल दिल्ली में आई बाढ़ की याद ताजा हो आई, जब लोगों के घरों में पानी घुस गया था और उन्हें बाहर तंबुओं में शरण लेनी पड़ी थी। बरसात में जलभराव से उपजी समस्याएं और ठंड तथा गर्मी में बेघरों की बड़ी तादाद में मौत होना दिल्ली के समुचित विकास की कमी को ही नहीं बयान करता, बल्कि मानवीय स्तर पर समाज में कम होती सामाजिकता और संवेदना की कमी को भी दर्शाता है।

आजादी के बाद से ही राजधानी के रूप में दिल्ली अनेक समस्याओं से जूझती रही है। जल माफिया की मनमानी, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कारकों और बहुत बड़े पैमाने पर झुग्गियों के रातोंरात खड़े हो जाने जैसी घटनाएं दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी और शहर के रूप में पहचान बनाने से रोकते रहे हैं। हर साल सर्दी और बरसात में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू, चिकनगुनिया, मौसमी बुखार, मलेरिया से सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। जलभराव की वजह से इन बीमारियों का फैलाव तेजी से होता है। इसलिए दिल्ली को समस्या मुक्त राजधानी के रूप में विकसित करने की जरूरत है।

जलभराव और अतिक्रमण के अलावा कूड़े-कचरे से पैदा होने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाने का काम महज सरकार से नहीं होगा। आम आदमी को भी अपनी आदतों, लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना हरकतों को छोड़ना होगा। कम क्षेत्रफल में ज्यादा आबादी का बोझ ढो रही दिल्ली में हर वर्ष बढ़ते लाखों वाहन भी दिल्ली की मौजूदा सड़कों और यातायात व्यवस्था की मौजूदा हालात को बदतर करने के जिम्मेदार हैं। जलभराव से ठप यातायात या जाम के हालात सड़क की क्षमता से बहुत ज्यादा वाहनों की वजह से पैदा होते हैं। इसलिए व्यक्तिगत वाहनों के इस्तेमाल की जगह सार्वजनिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जाम की वजह से दिल्ली में पर्यावरण की समस्या खतरनाक स्तर तक पहुंच जाती है। इसलिए सड़क, यातायात व्यवस्था, जल निकासी और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए दिल्ली वालों को भी आगे आना होगा।

फिर, दिल्ली की समस्याओं को दलगत भावना से ऊपर उठ कर देखने की जरूरत है। जब तक यह भावना नहीं आएगी कि दिल्ली हमारी है और इसकी हर समस्या को हल करने में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है तब तक दिल्ली को दुनिया की सर्वोत्तम राजधानी के रूप में विकसित नहीं किया जा सकता है।

अंदाज अपना अपना

दुनिया मेरे आगे

अमिताभ स.

हर इंसान दूसरे से जुदा होता है। कोई-कोई तो बचपन से ही बाएं हाथ से लिखता है, लेकिन उसके लिखने की रफ्तार दाएं हाथ से लिखने वालों से कम नहीं होती। ऐसे ही खब्बू बल्लेबाज भी चौके-छक्के लगाने या गेंदबाजी करने में पीछे नहीं रहते। यानी हरेक का अपना-अपना अंदाज होता है। कोई किसी से कम या पीछे नहीं होता। वह भी सही होता है और यह वाला भी। जमाना किसी को किसी दूसरे जैसा बनाने की कोशिश करे, तो भी खुद को बचाए रखना ही चाहिए। टीवी के पर्दे पर चलने वाले प्रतियोगिता आधारित कुछ 'रियलिटी शो' में प्रतियोगियों को वहां बैठे 'जज' भी आमतौर पर किसी की नकल न करने की हिदायत देते हैं और अपने ही अंदाज में अपनी कला का प्रदर्शन करने पर जोर देते हैं। हजारों गायक खुद को किशोर कुमार बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद का अपना अंदाज कायम रखना ज्यादा लंबी दौड़ का घोड़ा बनाने का दमखम रखता है।

प्राथमिक कक्षाओं से ही शिक्षक छात्र-छात्राओं को कुंजी या सहायक-पुस्तक की मदद न लेने की सलाह देते हैं। वजह साफ है कि अगर सभी परीक्षाओं में एक ही कुंजी से उत्तर रट कर लिखेंगे, तो सभी के औसत अंक ही आएंगे। बाकियों से हट कर उत्तर लिखने वाले ज्यादा अंक हासिल करते हैं। दरअसल, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है, जो रास्ता देखा-भाला और आसान लगता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वही रास्ता अव्वल आने के लिए सही ही हो। भीड़ के साथ बहने के बजाय अपनी राह खुद बनानी चाहिए, ताकि हम बाकियों से अलग हो सकें। हमेशा अलग बने रहना ही कामयाबी की वजह बनता है। जैसे आंखें झपकने-मटकाने की लाजवाब अदा ने हीरो राजेश खन्ना को रातोंरात सुपर स्टार बना दिया। यह उनकी अपनी शैली थी। ऐसा पर्दे पर पहले किसी ने नहीं किया था। कोशिश करके वही नहीं करना चाहिए, जो बाकी सभी करते हैं। कुछ अलग ढूंढ़ना चाहिए, फिर करना चाहिए। जो हट कर करता है, वह दूसरों से ज्यादा लाभ कमाता है।

> **भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है, जो रास्ता देखा-भाला और आसान लगता है। लेकिन जरूरी नहीं कि वही रास्ता अव्वल आने के लिए सही ही हो। भीड़ के साथ बहने के बजाय अपनी राह खुद बनानी चाहिए, ताकि हम बाकियों से अलग हो सकें।**

खलील जिब्रान की एक कहानी है। एक बार बदसूरती और खूबसूरती सागर में नहाने के लिए गईं। दोनों पानी में उतरीं। बदसूरती नहाकर पहले बाहर आ गई और खूबसूरती के कपड़े पहनकर चल दी। जब खूबसूरती बाहर आई, तो घबरा गई। अपनी लाज बचाने के लिए उसे आनन-फानन जो मिला, वही पहन लिया। अब उसके शरीर पर बदसूरती के कपड़े थे। लोग कपड़ों से धोखा खाकर बदसूरती को खूबसूरती और खूबसूरती को बदसूरती समझने लगे। हालांकि कुछ लोगों ने असली कपड़ों के साथ खूबसूरती का चेहरे भी देख रखा था। इसलिए बदले कपड़ों के बावजूद उसे पहचान ही लिया। इसी अपनी निजी खूबी से हरेक इंसान की खूबसूरती और दमक बरकरार रहती है। दुनिया के शीर्ष उद्योगपति जाहिर करते हैं कि जब कोई कारोबारी नया विचार आता है, जिसे सभी बेहतरीन मानें, तो उसे कचरे के डिब्बे में फेंकना बेहतर होता है, क्योंकि एकदम अलग-थलग और बिरले उपाय को चुनना और उसे अपने तरीके से करने-निभाने में जुट जाना कामयाब बनाता है। ऐसा करने से मुमकिन है कि मौजूदा वक्त में थोड़ी रिक्तता या दिक्कतें झेलनी पड़ें, लेकिन आने वाला दौर अत्यंत सुखद होता है।

खुद को बेमिसाल बनाने का एक तरीका है कि अपने अलग अंदाज में जारी रहना चाहिए। हर इंसान किसी खास काम के लिए बनाया गया है और उस काम को करने की इच्छा भी उसके अंदर भर दी गई है। बावजूद इसके कुछ को ही अपनी छिपी खूबी और काबिलियत का पता होता है। जैसे पीपल के वृक्ष की विशिष्टता है कि चाहे रेगिस्तान हो या बंजर स्थल, दलदल हो या सीमेंट की पक्की दीवार, वह कहीं भी और कभी भी अपनी जड़ें जमा लेता है। वह दूसरे पेड़ों की तरह नहीं है। इसीलिए पीपल प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना लेता है। हर इंसान में भी पीपल की वही जिजीविषा होनी चाहिए कि अपनी विशेष पहचान से उत्साह और जोश से भरा रहे। एक दर्शनशास्त्री की राय है कि मेरे पीछे मत चलिए, शायद मैं नेतृत्व न कर पाऊं। मेरे आगे न चलिए, शायद मैं पीछा करने में विफल रहूं। समझना चाहिए कि हर इंसान के लिए अलग-अलग जिंदगी बुनी गई है। अपने स्वभाव के अनुकूल रास्ते पर बढ़ने की जरूरत है। जरा देर से ही सही, सफलता अवश्य कदम चूमेगी।

बचपन में सुनी-पढ़ी कछुआ और खरगोश की कहानी में अब झोल या बदलाव आ चुका है। इसके घटनाक्रम में कछुआ खरगोश को सशर्त दौड़ के लिए चुनौती देता है। वह दौड़ का मार्ग अपने मुताबिक रखने को कहता है। आत्मविश्वास से भरा खरगोश झट मान भी जाता है। दौड़ के दौरान खरगोश उछलता- कूदता तेजी से तय स्थान की ओर दौड़ता है। लेकिन उस रास्ते में एक उफनती नदी बह रही होती है, जिस वजह से बेचारे खरगोश को वहीं रुकना पड़ता है। कछुआ धीरे-धीरे चलता वहां पहुंचता है। सरलता और सहजता से नदी पार कर लेता है। आगे लक्ष्य तक पहुंच कर जीत जाता है। सीख है कि पहले अपने स्वभाव, अंदाज और ताकत को पहचानना चाहिए। फिर उसके मुताबिक काम करने से जीत जरूर मिलेगी। लेकिन खयाल रहे कि कभी भी जल्दी या हड़बड़ी में जश्न नहीं मनाना चाहिए। जब तक हमारा उद्देश्य पूरा न हो जाए, तब तक अपनी भावनाओं पर काबू रखने की जरूरत है। पूर्व-परिपक्व जश्न अधिकतर निराशा में समाप्त होते हैं।

हिंसा की हवा

अमेरिका में बंदूक की छूट को देखते हुए कई बार ऐसा लगता है कि बंदूक चलाकर किसी को भी मारा जा सकता है। शायद बंदूक रखना वहां की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा बन गया है। लगभग हर तीसरे दिन वहां इस तरह की वारदात होती रहती है। बड़े तो बड़े, स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों द्वारा भी इस तरह का अपराध होना एक रोजमर्रा की बात हो गई है। हाल ही में जार्जिया के एक स्कूल में हुई घटना में दो छात्रों और दो शिक्षकों की मौत हो गई। नौ लोग घायल हुए। अधिकारियों ने एक चौदह वर्षीय छात्र को पकड़ा और कहा है कि इस पर एक बालिग की तरह मुकदमा चलाया जाएगा। चौदह वर्षीय छात्र को अगर सजा के तौर पर फांसी पर भी चढ़ा दिया जाएगा तो क्या अमेरिका में इस तरह के अपराध पर लगाम लग जाएगा? बंदूक संस्कृति के लिए वहां की दोनों पार्टियां रिपब्लिकन और डेमोक्रेट जिम्मेदार हैं। वहां बंदूक के धंधेबाजों की ओर से राजनीतिकों को मोटी रकम चंदे के रूप में मिलती है। सिर्फ स्कूलों में इस तरह के दिल दहला देने वाली हत्याओं का लंबी फेहरिस्त मौजूद है।

- जंग बहादुर सिंह, गोलपहाड़ी, जमशेदपुर

कानून के समांतर

सन 2012 के 'निर्भया कांड' ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद ऐसे अपराधों को रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त कानून लेकर आई थी। अब कोलकाता में एक प्रशिक्षु चिकित्सक की बलात्कार के बाद हत्या के बाद पश्चिम बंगाल ने केंद्र के मौजूदा कानून के समांतर 'अपराजिता विधेयक' पास किया है। मगर कानूनों का डर बलात्कारियों को कितना डरा रहा है, इसकी हकीकत राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो की रपट के हर वर्ष के आंकड़ों को देखकर पता चलती है। इस समस्या के हल के लिए कानूनी स्तर पर अधिकतम सख्ती के साथ कानून का डर कायम करना होगा, समाज के स्तर पर भी ऐसी विकास नीतियां लागू करनी होंगी, जिसमें इस समस्या की जड़ों की पहचान करके उसे दूर किया जा सके। रास्तों में रोशनी, कार्यस्थल पर सुरक्षा, पुलिस को संवेदनशील बनाने जैसे कारगर कदम उठाए बिना सभी कड़े कानून राजनीतिक शिगूफे साबित होते रहेंगे।

- मामचंद सागर, नई दिल्ली

जनता की पहुंच

वर्तमान दौर में अति आवश्यक दो मूलभूत सुविधाओं में महंगाई का रूप देखा जाए तो स्वास्थ्य और शिक्षा इतनी महंगी साबित हो रही है कि इसका उपभोक्ता बनने में मध्यम वर्ग और मजदूर वर्ग के कई लोग सक्षम नहीं हैं। शिक्षा में फीस की बढ़ोतरी आम जनता की सोच से परे लगती है। व्यक्ति दो जून की रोटी कैसे जुटाता है, वही जानता है। उस पर बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य में इतना पैसा लगता है। इस तरह निजी अस्पतालों में पीड़ित की पीड़ा दुगना करने में अस्पताल की भारी-भरकम फीस और अन्य जांच के शुल्क सीमा से ज्यादा होते हैं। कोई मापदंड ही नजर नहीं आता। सवाल है कि क्यों नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य को सेवाभावी होना चाहिए। आमजन की यह मूलभूत सुविधाओं में महंगाई जनता के सकारात्मक जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य सस्ते हों, जनता के लिए राहत भरे हों। ऐसी कारगर नीति तैयार करनी चाहिए। अन्यथा जनता इन मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाएगी।

- योगेश जोशी, बड़वाह

साख का सवाल

धनशोधन निवारण अधिनियम के तहत एक मामले की सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को आरोपी को दस्तावेज नहीं दिखाने के लिए जो फटकार लगाई, उसका संदर्भ उचित प्रतीत होता है। अदालत का आशय यह समझा जा सकता है कि दस्तावेज दिखाए बिना किसी पर भी आरोप कैसे लगाए जा सकते हैं? यह छिपा नहीं है कि अधिकांश आरोपी या तो अदालतों द्वारा दोषमुक्त करार दिए जाते हैं या फिर वे लंबी अवधि तक जेलों में बंद रहने के लिए मजबूर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस महत्त्वपूर्ण आदेश के दृष्टिगत ईडी को अपनी कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार करना चाहिए। आरोपियों को उनके अपराधों से संबंधित दस्तावेज मुहैया कराना चाहिए, ताकि वे भी अपने वैधानिक बचाव की तैयारी कर सकें। लोकतंत्र की मजबूती के लिहाज से इसे एक जरूरी कदम कहा जा सकता है।

- इशरत अली कादरी, भोपाल

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

दैनिक जागरण

अध्यात्म ही मन की शांति का आधार है

ट्रेनों के लिए खतरा

ट्रेन की पटरियों पर सीमेंट के ब्लाक, सिलेंडर, लोहे की छड़ें, पेड़ के मोटे तने आदि रखे जाने की घटनाएं महज दुर्योग नहीं हो सकतीं। ये घटनाएं किसी बड़ी साजिश का हिस्सा जान पड़ती हैं। इसकी आशंका इसलिए गहराती जा रही है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं जल्दी-जल्दी हो रही हैं। जहां कुछ घटनाओं में समानता देखने को मिल रही है, वहीं कुछ यह संकेत कर रही हैं कि उनके पीछे ट्रेन को पलटाने का इरादा था। उदाहरणस्वरूप रविवार को कानपुर-कासगंज के जिस ट्रैक पर कालिंदी एक्सप्रेस गुजरनी थी, उस पर एलपीजी भरा सिलेंडर रखा गया। लोको पायलट उसे देखकर जब तक ब्रेक लगाता, ट्रेन उससे टकरा गई। सौभाग्य से कोई क्षति नहीं हुई, लेकिन घटनास्थल पर जिस तरह पेट्रोल से भरी बोतल, बारूद जैसा पदार्थ, माचिस आदि मिली, उससे यही संदेह होता है कि यह आतंकी तत्वों का काम हो सकता है। इसी कारण इस मामले की जांच में एनआइए भी जुट गई। इसके पहले कानपुर के पास ही साबरमती एक्सप्रेस के ट्रैक पर सीमेंट के ब्लाक रख दिए गए थे। इससे इस ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इस घटना की जांच भी आतंकी घटना मानकर की जा रही है। कानपुर के समीप इसी तरह की एक अन्य घटना भी हो चुकी है। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी ट्रेनों को पटरी से उतारने की कोशिश के कई मामले सामने आ चुके हैं। गत दिवस अजमेर में मालगाड़ी को पटरी से उतारने के इरादे से ट्रैक पर 70-70 किलो के सीमेंट के ब्लाक रखे गए।

यह सही है कि कई बार शरारती तत्व रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़ करते हैं या फिर ट्रेनों पर पथराव कर देते हैं, लेकिन इधर ट्रेनों को जिस तरह निशाना बनाया जा रहा है, वह शुभ संकेत नहीं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि रेल पटरियों पर भारी वस्तु रखकर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को रेलवे ने आतंकी साजिश मानते हुए उन सभी की जांच का जिम्मा एनआइए को सौंप दिया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इन मामलों को गंभीर बता चुके हैं। यह ठीक है कि इन मामलों की जांच एनआइए कर रही है, लेकिन जब तक वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती, तब तक देश भर में पुलिस को विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इसके साथ ही आम लोगों को भी सावधान रहना होगा। उन्हें रेलवे ट्रैक के आसपास की गतिविधियों पर निगाह रखनी होगी और कुछ संदिग्ध या अस्वाभाविक दिखने पर संबंधित अधिकारियों को सूचना देने के लिए तत्पर रहना होगा। शरारती और आतंकी तत्वों के इरादों को नाकाम करने में आम लोगों को सहायक बनना ही चाहिए। निःसंदेह इस सबके साथ रेलवे को भी अपनी सतर्कता बढ़ानी होगी। उसे उन कारणों पर गौर करना होगा, जिनके चलते ट्रेनों को आसान निशाना समझ लिया गया है।

फर्जी जन्म प्रमाणपत्र

जिला पंचायत राज अधिकारी की जांच में अब यह पूरी तरह प्रमाणित हो गया है कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली की सलोन तहसील में बड़ी संख्या में फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाए गए थे, लेकिन सबसे गंभीर सवाल अभी तक अनुत्तरित है कि वे कौन लोग थे जिन्होंने इसे बनवाया। इस पूरे प्रकरण को केवल भ्रष्टाचार की दृष्टि से देखना गलत होगा। शुरुआती जांच में ही यह आशंका जताई गई थी कि कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को जन्म प्रमाणपत्र बनाकर न दिए गए हों। केवल रायबरेली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अमेठी और कुशीनगर जिले में भी फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनाने के मामले सामने आए थे, इसलिए इसे एक बड़ा अपराध मानते हुए इसकी व्यापक जांच कराई जानी चाहिए। यह अचरज की बात है कि किसी एक क्षेत्र में आबादी से अधिक लोगों के जन्म प्रमाणपत्र बना दिए जाएं और अधिकारियों के कानों पर जूं तक न रेंगे। किसी योजना का दुरुपयोग तभी संभव है, जब प्रशासनिक स्तर पर उसकी मानीटरिंग में उदासीनता बरती जा रही हो। तहसीलों में किस हद तक भ्रष्टाचार का घुन लगा है और पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है, सलोन की घटना इसका उदाहरण है।

जिला पंचायत राज अधिकारी की जांच रिपोर्ट के अनुसार 19,775 जन्म प्रमाण पत्रों में से 19,545 फर्जी पाए गए हैं। इसका मतलब है कि इन प्रमाणपत्रों का व्यापक स्तर पर दुरुपयोग किया जा सकता है। आतंकवाद निरोधक दस्ते ने इस पूरे प्रकरण में 17 लोगों को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन प्रमाणपत्र बनवाने वालों तक पहुंचकर ही इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जा सकता है। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी ऐसा किया जाना चाहिए। साथ ही, प्रदेश की हर तहसील में बनाए गए जन्म प्रमाणपत्रों की जांच कराई जाए। इस नजरिये से भी देखा जाए कि कहीं सरकारी योजनाओं का लाभ हासिल करने में तो इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है। अधिकारियों को ऐसे प्रमाणपत्रों को जल्द से जल्द निरस्त भी कराना होगा।

पड़ोसी देशों को साधने की चुनौती

हर्ष वी. पंत

दुनिया के किसी भी कोने में आदर्श पड़ोसी जैसी न तो कोई स्थिति है और न ही कोई आदर्श पड़ोस नीति। भारत भी इस मामले में अपवाद नहीं

आदर्श पड़ोस एक मिथ्या धारणा है। दैनिक जीवन में भी अपने पड़ोसियों से तालमेल बिठाने के लिए हमें तरह-तरह के पापड़ बेलने पड़ते हैं। पड़ोसियों के अभाव में भी हम अपूर्ण अनुभव करते हैं और उनकी उपस्थिति में उनके साथ धींगामुश्ती में लगे रहते हैं। ऐसा इसीलिए, क्योंकि अक्सर कई मसलों पर उनके साथ मेल-मिलाप मुश्किल होता है। हम उनके साथ जश्न भी मनाते हैं और छोटे-मोटे मुद्दों को लेकर नियमित आधार पर तकरार भी करते हैं। कुल मिलाकर पड़ोसियों के साथ सामंजस्य एक कड़ी चुनौती और रोजमर्रा की मशक्कत है। इस स्थिति से पार पाने का कोई एक कारगर मंत्र नहीं है। इसके लिए हमें निरंतर काम करना पड़ता है, ताकि अपने मन की शांति सुनिश्चित की जा सके। पड़ोसियों के मामले में जिन पेचीदगियों से आम लोग दो-चार होते हैं, वही स्थिति देशों के साथ भी होती है। कोई भी देश चाहे वह छोटा हो या फिर बड़ा, वह अपने पड़ोस को लेकर संघर्ष की स्थिति में ही दिखता है। इस मामले में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने यथार्थ ही कहा था, 'आप अपने मित्र चुन सकते हो, लेकिन पड़ोसी नहीं।' यही कारण है कि दुनिया के किसी भी कोने में आदर्श पड़ोसी जैसी न तो कोई स्थिति है और न ही कोई आदर्श पड़ोस नीति। इसमें और भी दिलचस्प पहलू यह है कि संबंध कई बार जितने अनुकूल दिखते हैं, उनकी मूल प्रकृति में प्रतिकूल पहलुओं की मौजूदगी की आशंका बनी रहती है। भारत का पड़ोस भी इस परिदृश्य से अलग नहीं।

जब भी भारत के किसी पड़ोसी देश में कुछ अप्रत्याशित घटता है तो कूटनीतिक-सामरिक हलकों में सवाल उठने लगते हैं कि आखिर इसकी कोई भनक क्यों नहीं लगी? मजे की बात यह है कि सवाल उठाने वाले स्वर मुख्य रूप से उन लोगों के होते हैं, जो अतीत में कूटनीतिक प्रतिष्ठान का हिस्सा रहे और उन्हें भी अपने उत्तराधिकारियों जितनी ही मिश्रित सफलता-असफलता हाथ लगी। हालांकि, वर्तमान की लानत-मलानत की प्रक्रिया में अतीत की बातों को विस्मृत कर दिया जाता है। समाधान के रूप में उन्हीं घिसे-पिटे सुझावों को सामने रखा जाता है, जिन्हें बीते सात दशकों के दौरान अलग-अलग तरीके से आजमाया जा चुका हो। इसका यह अर्थ नहीं कि आस-पड़ोस को लेकर भारत की नीतियां बिल्कुल माकूल हैं और उनके नीर-क्षीर विश्लेषण और समालोचना की आवश्यकता नहीं।

पड़ोस के संदर्भ में इस समय बांग्लादेश का मामला सबसे अधिक चर्चित है, क्योंकि बीते दिनों वहां सरकार को बेदखल किया गया। शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से बांग्लादेश भारी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। इस प्रकरण ने पड़ोस को प्रभावित करने को लेकर नई दिल्ली की सीमाओं को फिर से उजागर करने का काम किया है। बांग्लादेश में इतने बड़े पैमाने पर करवट ले रहे परिवर्तन का आकलन करने को लेकर यह मामला जितना भारतीय नौकरशाही और खुफिया तंत्र में समझ के अभाव से जुड़ा है, उतना ही बांग्लादेशी तंत्र पर भी सटीक बैठता है। एक लंबे समय तक संबंधों में गतिरोध के बाद बीते 15 वर्ष भारत-बांग्लादेश संबंधों के दृष्टिकोण से मील के पत्थर कहे जा सकते हैं। वर्षों की राजनीतिक उथल-पुथल के बाद बांग्लादेश ने भारत को लेकर अपनी पसंद का दांव चला और नई दिल्ली ने इन अनुकूल समीकरणों को हरसंभव तरीके से भुनाने का काम किया। बांग्लादेश की राजनीति में बीते डेढ़ दशक तक शेख हसीना के दबदबे से पहले ढाका के साथ भारत के रिश्ते बड़े कठिन दौर में थे और नई दिल्ली में शायद ही उसे लेकर कोई आशा की किरण दिखती थी। वहां एक बार फिर भारत विरोधी भावनाओं का ज्वार उठ रहा है। इस तथ्य को भी ओझल नहीं किया जा सकता कि पूर्व में बीएनपी सरकार के दौरान भारत-विरोधी रैलियों का आयोजन कितना आम हो गया था। इसी प्रकार मालदीव में इब्राहिम सोलिह के कार्यकाल के दौरान मिली सफलता पर मोहम्मद मुइज्जू के सत्ता में आने के स्तर पर मिली विफलता कहीं ज्यादा हावी दिखती है। इस बीच हमें यह भी याद रखना होगा कि महान राष्ट्र अपनी आधार भूमि पर मजबूती से टिके रहने के बावजूद उसकी परिधि से बाहर निकलकर कुछ गलतियों को नहीं दोहराते।

अवधेश राजपूत

पड़ोसी देशों के लिहाज से भारत की स्थिति हमेशा मुश्किल रही है और ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अपने आस-पड़ोस में भारत के वर्चस्व का कोई स्वर्णिम दौर भी रहा है। स्वतंत्रता के समय से ही जहां भारत के पड़ोसियों ने उसके कद के लिहाज से संतुलन बनाने का प्रयास किया, वहीं पाकिस्तान ने तो हमेशा खुद को भारत के बराबर प्रस्तुत करने के हरसंभव जतन किए। तमाम पड़ोसी देश समय-समय पर अन्य देशों के साथ संबंधों की पींगें बढ़ाकर भारत के साथ रिश्तों की दशा-दिशा तय करते रहे। भारत के बगल में चीन का उभार यही दर्शाता है कि उसके आर्थिक उभार के साथ ही भारत के पड़ोसियों की बीजिंग से गलबहियां उसी हिसाब से बढ़ती गईं।

भारत के पड़ोसियों की नियति मुख्य रूप से भारत द्वारा निर्धारित की जाएगी! हमारा यह आकलन जितना गलत है, उतना ही यह भी कि भारत की नियति को उसके पड़ोसी निर्धारित करेंगे। एक चुनौतीपूर्ण पड़ोस के बावजूद भारत के अंतरराष्ट्रीय कद और रसूख में निरंतर वृद्धि ही हुई है। भारत के उदय के समानांतर ही उसके कई पड़ोसी देश आर्थिक उतार-चढ़ाव से जूझते रहे। पड़ोस से जुड़ी भारत की नीति की आलोचना करते हुए हमें इन देशों की वस्तुस्थिति का भी संज्ञान लेना होगा। इसमें नई दिल्ली के प्रयास निश्चित रूप से एक पहलू हैं, लेकिन केवल यही एक पहलू सफलता को निर्धारित नहीं करेगा। तार्किक नीति यही कहती है कि भारत को अपने पड़ोस में निरंतर निवेश करते रहना चाहिए और साथ ही वह जागरूकता का यह भाव भी बढ़ाए कि इस निवेश का परिणाम उसके पड़ोसियों के हाथ में ही है। यदि अतीत के हिसाब से देखें तो ऐसे किसी निवेश पर बड़े प्रतिफल के आसार नहीं लगते। इसलिए, भारत की सफलता इसी पर निर्भर करेगी कि वह अपनी भौगोलिक परिधि के पहलू को किनारे रखकर एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने के पुरजोर प्रयास करे।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)

response@jagran.com

आतंक से लड़ने की कमजोर इच्छाशक्ति

राजीव सचान

उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या के एक आरोपित को जमानत मिलने से सवाल खड़े हो रहे हैं

देश में सिहरन पैदा करने वाले कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपित मोहम्मद जावेद को राजस्थान उच्च न्यायालय ने 5 सितंबर को यह कहते हुए जमानत दे दी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआइए उसके खिलाफ पर्याप्त प्रमाण नहीं जुटा सकी। उच्च न्यायालय के अनुसार, एनआइए ने जावेद की गिरफ्तारी काल डिटेल के आधार पर की, लेकिन वह उसकी लोकेशन नहीं दिखा सकी। जावेद को जमानत मिलने पर एनआइए के पास अपने पक्ष में कहने के लिए कुछ न कुछ अवश्य होगा, लेकिन उच्च न्यायालय के फैसले के बाद उसकी क्षमता पर सवाल तो खड़े ही हुए। यह गंभीर सवाल भी खड़ा हुआ कि आखिर इतने बर्बर हत्याकांड के दोषियों को सजा कब मिलेगी? खौफ पैदा करने वाली यह घटना जून 2022 में तब घटी थी, जब देश में 'गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सिर तन से जुदा..' के नारे लग रहे थे। ये नारे इसलिए लग रहे थे, क्योंकि तत्कालीन भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने टीवी पर बहस के दौरान शिवलिंग पर अपमानजनक टिप्पणी के जवाब में इस्लामिक मान्यताओं के बारे में एक तथ्यात्मक बात तंजपूर्ण लहजे में कह दी थी। इसका विरोध शुरू हुआ तो भाजपा ने उन्हें निलंबित कर दिया। इसलिए और भी, क्योंकि कतर एवं कुछ और इस्लामी देशों ने उनकी टिप्पणी पर आपत्ति जताई थी। देश के कई हिस्सों में सिर तन से जुदा के नारे लगाती हुई उन्मादी भीड़ सड़कों पर उतरी और उन लोगों को धमकाया जाने लगा, जो फेसबुक, वाट्सएप पर नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे थे।

नुपुर के समर्थन वाला एक संदेश उदयपुर के दर्जी कन्हैयालाल ने भी शेयर कर दिया था। इसका पता लगते ही उनके कुछ मुस्लिम परिचितों ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। उन्होंने वह संदेश डिलीट कर दिया और माफी भी मांग ली, लेकिन उन्हें धमकियां मिलनी बंद नहीं हुईं। उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो उसने उनका और उन्हें धमकाने वालों के बीच समझौता करा दिया, लेकिन जिहादी सोच वाले उनका गला काटकर ही माने। वे इतने दुस्साहसी थे कि उन्होंने इस वहशियाना हरकत का वीडियो बनाकर पोस्ट कर दिया। एक अन्य वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को भी धमकाया। यह स्वाभाविक है कि कन्हैयालाल हत्याकांड की चर्चा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुई। इसे आतंकी घटना मानकर जांच एनआइए को सौंप दी गई, लेकिन 26 महीने बाद पता चल रहा है कि वह कन्हैयालाल की हत्या की साजिश में शामिल रहे जावेद के खिलाफ पुख्ता प्रमाण नहीं जुटा सकी। इस मामले में कुल 11 लोग आरोपित बनाए गए थे। इनमें दो पाकिस्तानी भी थे, जो कन्हैयालाल का गला काटने वालों से एक वाट्सएप ग्रुप के जरिये जुड़े थे। इन पाकिस्तानियों का तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जिन्हें कन्हैयालाल की हत्या में गिरफ्तार किया गया, उन्हें तो अब तक सजा दिलाई ही जा सकती थी। वकीलों की मानें तो इस मामले में ट्रायल लंबा चलेगा और अभी कम से कम चार-पांच वर्ष और लग सकते हैं। पता नहीं आगे कब, क्या होगा, लेकिन इससे दयनीय और कुछ नहीं कि ऐसे जतन नहीं किए जा सके कि इतने गंभीर मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर हो सकती।

जेल से निकलता कन्हैयालाल हत्याकांड का आरोपित। प्रेट्र

कन्हैयालाल की तरह से अमरावती के उमेश कोल्हे की भी नुपुर शर्मा का समर्थन करने के 'अपराध' में हत्या कर दी गई थी। जैसे यह पता नहीं कि कन्हैयालाल के हत्यारों को कब सजा मिलेगी, वैसे ही यह भी जानना कठिन है कि उमेश कोल्हे के हत्यारे कब सजा पाएंगे। ऐसे मामलों के निस्तारण में देरी इसलिए निराश और चिंतित करने वाली है, क्योंकि देश में जिहादी तत्वों की गतिविधियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीते दिनों ही यह खबर आई कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाका करने वाले आतंकियों ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भाजपा के कार्यालय में विस्फोट करने की योजना बना रखी थी। ये आतंकी इस्लामिक स्टेट से प्रेरित थे और उन्होंने अल-हिंद नाम से अपना आतंकी संगठन बना रखा था। देश में इस तरह के न जाने कितने संगठन हैं। कोई इस्लामिक स्टेट के बताए रास्ते पर चल रहा है तो कोई अलकायदा, लश्कर-ए-तोइबा आदि के रास्ते पर। यह भी किसी से छिपा नहीं कि पीएफआइ जैसे आतंकी संगठनों पर भारत को इस्लामी देश बनाने की सनक सवार है। इन स्थितियों में होना यह चाहिए कि आतंकियों, जिहादियों को प्राथमिकता के आधार पर जितनी जल्दी संभव हो, सजा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। आश्चर्य नहीं कि इसी के चलते नुपुर शर्मा को अभी भी सुरक्षा के साये में नजरबंदी जैसा जीवन जीना पड़ रहा है।

कन्हैयालाल हत्याकांड के एक आरोपित को जमानत मिलना इसलिए और निराशाजनक है, क्योंकि राजस्थान विधानसभा चुनाव के अवसर पर एक चुनावी रैली में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि राजस्थान में खुलेआम गला काट दिया जाता है और सरकार देखती रहती है। उनके निशाने पर तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार थी। इस पर हैरानी नहीं कि कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपित को जमानत मिल जाने से अशोक गहलोत को यह कहने का मौका मिला कि भाजपा ने चुनावी लाभ के लिए इस हत्याकांड का राजनीतिक इस्तेमाल किया, किंतु केंद्र सरकार की एनआइए ने दोषियों को सजा दिलाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। इस राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच कन्हैयालाल के परिवार वालों और विशेष रूप से उनके बेटे का निराश होना समझ आता है, जिसने यह संकल्प ले रखा है कि जब तक उसके पिता के हत्यारों को फांसी की सजा नहीं मिलती, तब तक वह नंगे पैर रहेगा और पिता की अस्थियों का विसर्जन भी नहीं करेगा। यह अधूरा संकल्प आतंक से लड़ने की हमारी कमजोर इच्छाशक्ति का ही परिचायक है।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

मार्गदर्शक सूत्र

समग्र विश्व को सनातन धर्म की आभा से अभिभूत करने वाले स्वामी विवेकानंद ने मानव जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के कई उपयोगी सूत्र भी सुझाए हैं। ऐसा ही एक सूत्र कठोपनिषद से 'उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत' के रूप में दिया। इसके माध्यम से उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति तक निरंतर प्रयास करने का संदेश दिया है। आज के भौतिक एवं प्रतिस्पर्धी युग में हर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पाने के लिए दौड़ रहा है। जीवन में प्रायः हम अपने उद्देश्य और आंतरिक शक्ति को भूलकर तकनीक और आधुनिकता की उलझनों में फंस जाते हैं। इससे भटकाव की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद की दिखाई गई राह अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकती है।

स्वामी जी ने कहा है कि 'उठो', अर्थात अपने भीतर छिपी हुई शक्तियों को पहचानो और आलस्य छोड़कर सक्रिय रूप से कार्य करो। 'जागो' का अर्थ है अपनी चेतना का विस्तार करो। जब हम सीमित धारणाओं और विचारों में फंसे रहते हैं तो हमारा विकास रुक जाता है। यदि आपके कार्य में कोई चुनौती नहीं आई, तो समझिए कि आप गलत राह पर हैं। हमें इन चुनौतियों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता से हम सही निर्णय ले सकते हैं और लक्ष्य प्राप्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। वस्तुतः, असफलताओं से विचलित होने पर जागरूकता हमें धैर्य और समर्पण के साथ अपने काम में निरंतर लगे रहने की प्रेरणा देती है। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति स्पष्ट और जागरूक होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। आत्मविश्वास ही सफलता का मूल आधार है।

स्वामी विवेकानंद का संदेश सिर्फ आत्मविकास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए भी प्रेरित करता है, जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक सूत्र है।

सोमा सुर

जलवायु विस्थापन का बढ़ता खतरा

सुधीर कुमार

जलवायु परिवर्तन के कारण 2050 तक विश्व में 21 करोड़ लोगों को अपने देश के भीतर ही विस्थापित होना पड़ेगा

जलवायु परिवर्तन के खतरे के कारण अपने द्वीपीय समुदाय को स्थानांतरित करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है पनामा। दरअसल पनामा के कैरिबियन सागर में स्थित 'गार्डी सुग्दुब' द्वीप पर बसे एक हजार से अधिक 'गुना' समुदाय के लोग बढ़ते समुद्री जलस्तर और इससे उत्पन्न बाढ़ और जलप्लावन के गंभीर खतरे का सामना कर रहे थे। जलवायु परिवर्तन के कारण संकट में पड़ी उनकी संस्कृति, आजीविका और जीवनशैली की सुरक्षा तथा संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उन्हें मुख्य भूमि पर स्थानांतरित करके नवनिर्मित घरों में बसाया गया। यह घटना वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहे मानवीय स्थानांतरण और विस्थापन की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करती है। यह इस बात की भी पुष्टि करती है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संगठित कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ने की आशंका है।

जलवायु परिवर्तन के कारण विस्थापन की यह कोई पहली घटना नहीं है। परंतु ऐसा पहली बार हुआ है, जब जलवायु परिवर्तन के कारण एक द्वीप के सभी निवासियों को स्थानांतरित होना पड़ा है। जलवायु परिवर्तन और मानवीय विस्थापन के बीच घनिष्ठ संबंध है। जलवायु परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली चरम मौसमी घटनाएं लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर करती हैं। अंतरराष्ट्रीय विस्थापन निगरानी केंद्र के अनुसार, वर्ष 2008 से 2022 के बीच जलवायु विस्थापन की घटनाओं में 41 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसी लगभग 98 प्रतिशत घटनाएं बाढ़, तूफान और सूखे जैसी मौसम संबंधी खतरों के कारण हुई हैं। इसी साल अप्रैल-जून में ब्राजील में आई बाढ़ के कारण कम से कम 3.86 लाख लोग विस्थापित हुए थे। विश्व प्रवासन रिपोर्ट-2024 बताती है कि जलवायु परिवर्तन 2050 तक 21.6 करोड़ लोगों को अपने देश के भीतर ही स्थानांतरित होने के लिए मजबूर करेगा।

जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभावों के कारण अपने घरों और समुदायों को छोड़ने वाले लोगों के लिए वर्ष 1976 में लेस्टर ब्राउन ने सर्वप्रथम 'पर्यावरण शरणार्थी' शब्द प्रस्तुत किया था। बाद में इसके लिए 'जलवायु शरणार्थी' शब्दावली का भी इस्तेमाल होने लगा। जलवायु शरणार्थियों को खाद्य एवं जल असुरक्षा, अकेलापन, आजीविका का खतरा, संघर्ष, उत्पीड़न और बीमारी आदि का सामना करना पड़ता है। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के पार और भीतर होने वाला उनका प्रवाह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करता है।

बहरहाल, जलवायु परिवर्तन की दिशा में ठोस कदम उठाकर ही ऐसे मामलों में कमी लाई जा सकती है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

मेलबाक्स

सार्थक राजनीति की आवश्यकता

'राहुल गांधी के विचार' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय में उनकी अमेरिका यात्रा के दौरान प्रवासी भारतीयों के समक्ष व्यक्त उनके उद्गार देशवासियों के सामने आए। वह नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनकी बातें जिम्मेदारी से भरी नहीं लगतीं। गैर हिंदी भाषियों पर हिंदी थोपने और भाजपा एवं आरएसएस पर महिलाओं को दबाए जाने संबंधी उनकी बातें निःसंदेह अटपटी हैं। उन्होंने अमेरिकी धरती पर प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बहुत स्वाभाविक भी है। हालांकि, उनकी बातों में सरकारी नीतियों की आलोचना कम, बल्कि दुनिया वालों को यह बताने की आतुरता अधिक थी कि भारत में संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। सवाल है कि यदि ऐसा होता तो क्या राहुल और कांग्रेस का कोई नेता इतनी मुखरता से देश-विदेश में अपनी बात रख पाने में सफल होते। बेहतर हो कि हमारे नेतागण कोरी बयानबाजी छोड़कर राजनीतिक परिपक्वता का परिचय देकर सार्थक राजनीति की दिशा में आगे बढ़ें।

मुकेश कुमार मनन, पटना

स्वच्छ भारत अभियान की सफलता

'सशक्तीकरण का माध्यम बना स्वच्छता अभियान' शीर्षक से प्रकाशित आलेख में डा. ऋतु सारस्वत ने महिला सशक्तीकरण और स्वच्छता का सुव्यस्थित अंतर्संबंध प्रस्तुत किया है। उन्होंने इस बात पर विशेष ध्यान दिया है कि किस प्रकार एक शौचालय न केवल महिला के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, बल्कि उनके आत्मसम्मान की भी रक्षा करता है। अच्छी बात यह रही कि इस अभियान के परिणामस्वरूप महिलाओं के जीवनस्तर की गुणवत्ता और उनकी जीवन प्रत्याशा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लेखिका ने इसका विशेष रूप से उल्लेख किया है कि इस कार्य में हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का महत्वपूर्ण योगदान है। मालूम हो कि प्रधानमंत्री ने ही 15 अगस्त 2014 को लाल किले से देश को संबोधित करते हुए महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी, जिसका एक व्यापक असर दिखाई दिया। इस अभियान में लोगों की जन भागीदारी बढ़ी जिससे इसे सफलता की ओर अग्रसर किया। ऐसे में यह मात्र एक राजनीतिक उद्घोषणा न रहकर जन-जन का मूलमंत्र बन गया जिसका परिणाम है कि देश के लगभग सभी गांव अपने आप को खुले में शौच मुक्त घोषित कर चुके हैं। जिसका सीधा सकारात्मक प्रभाव हमारे देश की महिलाओं पर पड़ा है। एक रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ने वर्ष 2011 से 2020 के बीच भारत में सालाना 60 से 70 हजार शिशुओं की मृत्यु को रोकने में मदद की है जो स्वयं में इस मिशन की सफलता का वर्णन करता है। तथापि हमें अभी यहां रुकना नहीं है, हमारी यात्रा निरंतर जारी रहनी चाहिए, जिससे हम जमीनी स्तर पर जाकर वहां एक सकारात्मक बदलाव ला सकें और अपने देश को इसके दुष्प्रभाव से पूर्णतया मुक्त कर सकें और यही वर्तमान समय की मांग भी है।

गुलशन स्वामी, फरीदाबाद

भारत की डिजिटल क्रांति

प्रत्येक भारतीय के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है कि भारत दुनिया में डिजिटल लेन-देन में पहले स्थान पर है। विश्व के कुल डिजिटल ट्रांजेक्शन में भारत की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से भी अधिक की है। भारत के यूपीआइ (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) ने अमेरिका के पे-पल तथा चीन के अली-पे को पछाड़ कर अप्रैल से जुलाई तक 81 लाख करोड़ रुपये का डिजिटल लेन-देन किया है, जो पिछले साल की तुलना में 37 प्रतिशत से भी अधिक है। आज भारत में सब्जी का ठेला लगाने वाले से लेकर बड़े-बड़े उद्योगपतियों की पहली पसंद यूपीआइ है। भारत में आई यह डिजिटल क्रांति दुनिया के लिए आज मिसाल बन चुकी है। भारत सरकार के देश को पांच लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में जुटी हुई है। यूपीआइ इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण टूल के रूप में उभरकर सामने आया है। लिहाजा हमारा देश डिजिटल क्रांति की ओर अग्रसर है।

आशुतोष ठाकुर, अमृतसर

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सैक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक- स्व. पूर्णचन्द गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक- संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सैक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

88 प्रतिशत जीएम फसलों को शाकनाशी (हर्बिसाइड) के प्रति सहनशील बनाया गया है। यानी जीएम फसलें आम तौर पर शाकनाशियों के उपयोग को बढ़ाती हैं, जिससे इनकी विषाक्तता बढ़ जाती है।

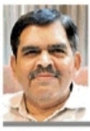

डा. अश्विनी महाजन
पूर्व-प्रोफेसर, पीजीडीएवी कालेज, दिल्ली विश्वविद्यालय

आजकल

आसान नहीं दिख रहा जीएम पर नीति बनाना

उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में देश में जीन संवर्धित (जीएम) सरसों की व्यावसायिक खेती के संबंध में एक विभाजित निर्णय दिया है। जहां एक न्यायाधीश ने अनुमोदन प्रक्रिया में खामियों और पर्यावरण एवं इसके स्वास्थ्य दुष्प्रभावों पर पर्याप्त विचार-विमर्श की कमी का हवाला देते हुए जीएम सरसों की व्यावसायिक बिक्री के विरुद्ध निर्णय सुनाया, तो वहीं एक अन्य न्यायाधीश ने सख्त सुरक्षा उपायों के साथ इसका फील्ड ट्रायल जारी रखने का समर्थन किया। ऐसे में लंबे समय से विवादों में रहा जीएम फसलों का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है

खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए जीएम सरसों के विकल्प पर भी ध्यान देने की बात कही जा रही है। प्रतीकात्मक

जीएम फसलों की व्यावसायिक खेती से संबंधित एक मामला (सुमन सहाय और अरुणा रोड्रिग्स एवं अन्य बनाम भारत सरकार एवं अन्य) वर्ष 2004 से सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है, लेकिन जीएम फसलों के पैरोकार जीएमओ की व्यावसायिक रिलीज के लिए अदालत की मंजूरी अभी तक नहीं ले पाए। इस मामले से कई विवादास्पद मुद्दे जुड़े हैं, जिन पर अदालत अब तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है। लगभग एक माह पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया विभाजित निर्णय एक बार फिर इस मामले की जटिलताओं को दर्शाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया कि वह इस नीति को तैयार करने के लिए चार महीने के भीतर सभी हितधारकों और विशेषज्ञों से परामर्श करे। साथ ही, पीठ ने मामले को उचित पीठ द्वारा आगे के निर्णय के लिए मुख्य न्यायाधीश के पास भेज दिया है। हालांकि न्यायालय ने सरकार को विभिन्न हितधारकों और विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद चार महीने के भीतर जीएम पर एक नीति तैयार करने का निर्देश दिया है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिसने देश और दुनिया में पिछले 25 साल से अधिक समय से भारी बहस और गर्माहट पैदा की है, जहां विशेषज्ञ एकमत नहीं हैं। लोग जीएम के दुष्प्रभावों के कारण डरे हुए हैं। एक मजबूत नियामक तंत्र का पूर्ण अभाव है, जहां सर्वोच्च न्यायालय स्वयं नियामक तंत्र की कमी के कारण इस जीएम के पक्ष में निर्णय देने के लिए तैयार नहीं है, वहीं जीएमओ के मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के भी सबूत नहीं हैं। वैसे कई देशों ने मानव स्वास्थ्य व पर्यावरण की चिंताओं के कारण पहले ही जीएम फसलों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, लिहाजा इस बात की संभावना कम है कि सरकार विशेषज्ञों के साथ परामर्श के बाद चार महीने में जीएम पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने का यह कार्य पूरा कर पाएगी।

ऐसा नहीं है कि जीएम फसलों के लिए पहली बार परामर्श तंत्र अपनाया जा रहा है। इससे पहले, यूपीए सरकार के दौरान बीटी बैंगन के वाणिज्यिक विमोचन के संबंध में तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्री जयराम रमेश के साथ सार्वजनिक सुनवाई हुई थी। यह ध्यान देने योग्य है कि इन सार्वजनिक सुनवाई के अंत में जयराम रमेश ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए बीटी बैंगन के वाणिज्यिक प्रयोग पर रोक लगा दी थी।

क्या हो परामर्श की उचित संरचना : सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को हितधारकों और विशेषज्ञों के परामर्श आयोजित करने का निर्देश दिया है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इन परामर्शों की संरचना क्या हो सकती है। ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर ये परामर्श हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तकनीकी विशेषज्ञ समिति द्वारा कई विवादास्पद मुद्दों को लंबे समय से सूचीबद्ध किया गया है, जो परामर्श प्रक्रिया का आधार बन सकते हैं और निष्कर्ष पर पहुंचने में मदद कर सकते हैं।

सबसे पहला मुद्दा, जिस पर विशेषज्ञों के बीच आम सहमति का अभाव है, वह जीएम फसलों की उच्च उत्पादकता का दावा है। दिलचस्प बात यह है कि सरकार और जीएम समर्थकों का तर्क यह है कि देश बड़ी मात्रा में खाद्य तेलों का आयात कर रहा है, जिनमें से अधिकांश जीएम तेल हैं। सरकार का दावा है कि डीएमएच 11 को अपनाने से आयात पर निर्भरता कम करने और डीएमएच 11 की अधिक उत्पादकता के कारण किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है। लेकिन जबकि डीएमएच 11 के डेवलपर (अनुसंधानकर्ता) के अनुसार भी इसकी उत्पादकता 2200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से अधिक नहीं है, जबकि देश में सरसों की कई अन्य संकर किस्मों की अपेक्षित उपज ढाई हजार किलोग्राम से चार हजार किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक है। विवाद का दूसरा मुद्दा बौद्धिक संपदा अधिकारों का है। किसान संगठनों को चिंता है कि एक बार जीएमओ अपनाने के बाद, बीज पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकाधिकार हो जाएगा और किसानों पर बीजों पर रायल्टी के रूप में बोझ बढ़ जाएगा। उनकी आशंकाएं बेवजह नहीं हैं। हम देखते हैं कि किसानों को असफल बीटी कपास के बीज के लिए भी बहुत अधिक कीमत (आठ हजार करोड़ रुपये) चुकाने पड़े, क्योंकि बीटी कपास के बीज की कीमत का एक बड़ा हिस्सा विशेषता शुल्क था।

तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर उनका प्रभाव है। जबकि जीएम के समर्थक बिना किसी वैध तर्क के दावा करते हैं कि इससे आयातित खाद्य तेलों पर हमारी निर्भरता कम हो जाएगी (यदि डीएमएच 11 को अनुमति दी जाती है), तथ्य यह है कि खाद्य फसलों में जीएम अपनाने के बाद हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी अपना लाभ खो सकते हैं। चौथा विवादास्पद मुद्दा जीएम बीजों के भारतीय खाद्य और आयुर्वेद पर प्रभाव के बारे में है। जीएम फसलें खाद्य पदार्थों की उपलब्धता को बदल देती हैं, जो हमारे भोजन का आवश्यक हिस्सा हैं। उदाहरण के लिए सरसों का साग। भारतीय सरसों के आयुर्वेद में कई औषधीय उपयोग हैं, जिन्हें हम खो सकते हैं।

जीएमओ पर बहस में पांचवां मुद्दा शाकनाशी सहिष्णुता है। यह उल्लेखनीय है कि लगभग 88 प्रतिशत जीएम फसलों को शाकनाशी (हरबिसाइड) सहनशील बनाया गया है। इसका मतलब है, जीएम फसलें आम तौर पर शाकनाशियों के उपयोग को बढ़ाती हैं, जिससे विषाक्तता बढ़ जाती है। लगभग सभी प्रमुख शाकनाशी कैंसरकारी साबित हुए हैं। यह बहुत खेद की बात है कि जीएम सरसों के शाकनाशी सहनशील होने के तथ्य को शुरू में छुपाया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि डीएमएच 11 का परीक्षण करते समय, इसकी शाकनाशी सहिष्णुता के बारे में कोई परीक्षण नहीं किया गया था। जब जागरूक नागरिकों और विशेषज्ञों ने जीईएसी के इस कृत्य को उजागर किया तो समिति ने हास्यास्पद शर्त लगा दी कि किसी भी स्थिति में किसान खरपतवारनाशकों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। विवादास्पद मुद्दों की सूची में कई बिंदु शामिल हैं, जिन पर विचार किए बिना हम इस विषय पर एक समझ पूर्ण नीति बनाने के अपने कर्तव्य में विफल हो सकते हैं। इन मुद्दों में बीज संप्रभुता और जैव विविधता पर प्रभाव, उपभोक्ता संरक्षण और विकल्पों पर प्रभाव, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संप्रभुता और पोषण सुरक्षा पर प्रभाव, हितों के टकराव का मुद्दा (यदि हम देखें कि जीएम को अपनाने की सिफारिश करने वाले लोग वास्तव में जीएम के डेवलपर्स से जुड़े हैं), स्वतंत्र परीक्षण का अभाव और खरपतवारनाशकों के प्रति सहनशील जीएमओ के उपयोग से संबंधित सामाजिक-आर्थिक विचार और मधुमक्खियों पर इनके दुष्प्रभाव शामिल हैं।

सबसे तेज गति से आगे बढ़ेगी हमारी आर्थिकी

प्रह्लाद सबनानी

वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून 2024) में सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर के आंकड़े हाल ही में जारी किए गए हैं। हर्ष का विषय यह है कि भारत अभी भी विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था बना हुआ है। वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में 8.2 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज हुई थी तथा पिछली तिमाही (जनवरी-मार्च 2024) में वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत की रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल-जून 2024 तिमाही में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया था।

भारत में वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में जीडीपी में कम हुई वृद्धि दर के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं। इस तिमाही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं जिस दौरान केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिसके चलते सरकारों को अपने खर्चों को नियंत्रण में रखना होता है। दूसरे, इस तिमाही के दौरान देश में अत्यधिक गर्मी के चलते पर्यटन एवं कृषि के क्षेत्र में विकास दर कम हो गई। कृषि के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में वृद्धि दर केवल दो प्रतिशत की रही है जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही में 3.7 प्रतिशत की रही थी। परंतु चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही में लगभग पूरे देश में मानसूनी बारिश हुई है, अतः विभिन्न फसलों की बोआई के क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज हुई है। इसलिए कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर के आकर्षक रहने की संभावना व्यक्त की जा रही है। खरीफ मौसम की फसल के साथ ही अब रबी की फसल में भी अच्छी वृद्धि दर रहने की संभावना है, क्योंकि देश के विभिन्न जलाशयों में पानी के संचयन में भारी वृद्धि दर्ज हुई है, जिसे कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए उपयोग किया जा सकेगा।

विनिर्माण सेक्टर द्वारा किए गए उत्पादन में अप्रैल-जून 2024 की तिमाही में सात प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। निर्माण के क्षेत्र में 8.6 प्रतिशत एवं सेवा के क्षेत्र में 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, होटल, टेलिकाम की ग्रोथ 5.7 प्रतिशत की रही है। विनिर्माण, निर्माण एवं कोर इंडस्ट्री को मिलाकर बनने वाले सेकेंडरी सेक्टर में वृद्धि दर बढ़ी है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की प्रथम तिमाही में यह 5.9 प्रतिशत की रही थी, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही में बढ़कर 8.4 प्रतिशत की हो गई है। यह वृद्धि दर देश में निजी उपभोग बढ़ने की ओर इशारा करती है। लंबे समय से जारी दो युद्धों के बीच भारत की उक्त आर्थिक विकास दर अच्छी ही कही जाएगी।

यूरोप में कुछ देशों की आर्थिक विकास दर में कमी होती दिखाई दे रही है। जापान एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्थाओं में भी विकास दर में कमी आंकी गई है। जापान एवं जर्मनी में यदि विकास की रफ्तार कम होती है एवं भारत की आर्थिक विकास दर इसी रफ्तार से आगे बढ़ती है तो भारत, जापान एवं जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। **(लेखक आर्थिक मामलों के जानकार हैं)**

खरी-खरी

गणपति बप्पा की सेल्फी भक्ति

प्रभुनाथ शुक्ल

हमारे धर्मशास्त्र में भक्ति के नौ स्वरूपों का वर्णन किया गया है, लेकिन बदलते दौर में यह नब्बे से अधिक रूपों में समाहित है। आजकल सबसे अधिक सेल्फी और राष्ट्रभक्ति का बोलबाला है। क्या मजाल कोई इस भक्ति पर सवाल उठा दे। अगर कोई उठाता भी है तो वह सीधे राष्ट्रद्रोही एवं सेल्फी विरोधी बन सकता है। दूसरे नंबर पर राजनीति और राजनेताओं की भक्ति है। इसी भक्ति का प्रतिफल है कि लोग घंटों और मिनट में दल और दिल बदल रहे हैं। इस भक्ति का खूब जलवा है।

तीसरे नंबर पर धर्म और संप्रदाय की भक्ति हमारे देश में खूब बिकती है। लिहाजा सरकार को धर्मावलंबियों की मीटिंग बुलाकर धर्म संसद में भक्ति के नौ रूपों में से एक रूप को और जोड़ने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। जब से मोबाइल युग का दौर चला है, एक नई भक्ति का प्राकट्य हुआ है। उस दसवीं भक्ति का नाम है सेल्फी भक्ति। जी हां! देश में आजकल इस भक्ति का बेहद बोलबाला है। नभ से लेकर जमीन तक जहां भी जाइए सेल्फी भक्ति को पाइएगा। देवालय, सागर, नदियां, झरने, कार्यस्थल, बाढ़, सूखा, रेलयात्रा, पिकनीक हर स्पाट पर यह भक्ति साथ-साथ होती है।

आजकल देश भर में गणपति बप्पा की धूम है। जिसकी वजह से सेल्फी वाले भक्तों का जलवा है। मुंबई में तो बप्पा की सेल्फी लेने की होड़ मची है। भक्ति के बदले स्वरूप को देखते हुए पूरे पंडालों में सेल्फी प्वाइंट बना दिए गए हैं। भक्तों को कोई दिक्कत न हो और आराम से भक्त बप्पा की सेल्फी लें और फिर उसे इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर लिखें कि आज हमने अपूतपूर्व भक्ति की है। बप्पा भी ऐसे भक्तों से परेशान हैं। भक्त उनकी आराधना के लिए नहीं, केवल सेल्फी के लिए घंटों लाइन लगा रहे हैं। बप्पा को आराम करने का अवसर नहीं मिल रहा है। बप्पा मूसकराज पर विराजमान हैं। बेचारे वह भी परेशान होकर कह रहे हैं कि प्रभो हमें भी लड्डू ग्रहण करने दीजिए। आप तो भक्तों के साथ सेल्फी मोड में हैं, हमें भी भूख-प्यास लगती है। हे प्रभो! ऐसी भक्ति से तौबा कीजिए।

X पोस्ट

मायावती इकलौती नेता है, जो देश में रेल दुर्घटनाओं को षड्यंत्र बताने का साहस रखती है। जांच और कार्रवाई की मांग करती है। अनुपम मिश्रा@scribe9104

सैम पित्रोदा ने कहा कि राहुल गांधी 'पप्पू' नहीं हैं, मगर राहुल के बयानों से लगता है कि वह पित्रोदा को गलत साबित करने में पूरी शिद्दत से जुटे हैं। उनकी चंद दिनों की अमेरिका यात्रा साल भर का मसाला देने के लिए पर्याप्त लग रही है।
अभिजीत अय्यर मित्रा@Iyervval

मैं एक सिख हूं। मैं देश में कहीं भी कड़ा और पगड़ी पहन कर जाता हूं। मुझे कहीं भी, किसी ने भी अपने धार्मिक प्रतीकों की वजह से रोका-टोका नहीं। मैं अपने देश में खुश हूं और राहुल गांधी से अनुरोध करता हूं कि अपनी विषैली महत्वाकांक्षाओं के लिए सिखों का सहारा लेना बंद कर दें।
लकी सिंह@luckyschawla

चाहे फिल्में हों या वेब सीरीज, ऐतिहासिक घटनाओं पर बनने वाली सामग्री को सेंसर से होकर ही जाना चाहिए। शुरू में चींटी बराबर फांट में डिस्क्लेमर में लिख देते हैं- 'यह सीरीज सच्ची घटनाओं से प्रेरित है' अंदर अपने हिसाब से तथ्यों को छिपाया व तोड़-मरोड़ा जाता है। इससे देश को जो नुकसान हो रहा है, सब जानते हैं।
मानक गुप्ता@manakgupta

इन्द्रप्रीत सिंह
ब्यूरो प्रमुख, पंजाब

पंजाब डायरी

सब्सिडी : बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे

पिछले दिनों एक चर्चा के दौरान एक वरिष्ठ राजनेता से बातचीत हुई। बातचीत के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि सब्सिडी को तर्कसंगत करने पर सभी राजनीतिक पार्टियों में सहमति क्यों नहीं बन पाती है। उनका तर्क था कि जो भी पार्टी किसी सब्सिडी को खत्म करना चाहेगी, चुनाव में उस पार्टी का बुरा हाल हो जाएगा। उन्होंने दलील दी कि वर्ष 2002 में कैप्टन अमरिंदर ने सभी प्रकार की सब्सिडियां खत्म कर दीं। लेकिन बाद में जब 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी बुरी तरह से हारी तो सभी सीनियर नेताओं ने कैप्टन द्वारा सब्सिडियां बंद करने को इसका कारण बताया। यह दबाव इतना था कि आखिरकार एक एक करके उन्होंने सभी सब्सिडियां देने शुरू कर दीं। सब्सिडी दोबारा शुरू करने का परिणाम भी उनके पक्ष में नहीं आया। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए कोई भी पार्टी सब्सिडी को बंद करने की हिम्मत नहीं दिखाएगी।

क्या यह तर्क सही है? अगर पिछले चुनावों के परिणामों पर इस तर्क को परखा जाए तो यह सही नहीं लगता। वर्ष 1997 में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने खेती के लिए निशुल्क बिजली देने का फैसला किया। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शिअद के साथ गठजोड़ में थी। लंबे अर्से बाद सत्ता में लौटे प्रकाश सिंह बादल ने जो फैसला लिया, उस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता बलरामजी दास टंडन की कैबिनेट की बैठक में ही टिप्पणी थी कि अब अकाली भाजपा गठजोड़ की सरकार 25 साल तक नहीं जाएगी। निशुल्क बिजली के चलते किसानों का वोट अकाली दल को ही मिलेगा और भाजपा के शहरी वोट से सरकार में हमेशा अकाली दल-भाजपा की ही बनेगी। लेकिन टंडन साहिब की यह टिप्पणी मात्र एक साल में ही गलत साबित हुई, जब 1998 के मध्यावधि चुनाव में गठजोड़ बुरी तरह से हार गया।

प्रकाश सिंह बादल। फाइल

अमरिंदर सिंह। फाइल

भगवंत मान। फाइल

राजनीतिक पार्टियों की जीत हार में सब्सिडियों का कोई लेना देना नहीं होता। इसका दूसरा बड़ा उदाहरण हालिया लोकसभा चुनाव है जिसमें आम आदमी पार्टी ने घरेलू सेक्टर को 300 यूनिट निशुल्क बिजली दी। खजाने पर 7800 करोड़ रुपये का नया बोझ पड़ गया। इसी तरह आठ सौ के आसपास मोहल्ला क्लीनिक खोलने का भी दावा किया गया जिसमें लोगों को हर किस्म का मुफ्त इलाज, दवाएं टेस्ट आदि भी निशुल्क है। मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने इन्हीं फैसलों को लेकर लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 13 सीटों पर जीत हासिल करने का दावा करने लगे। जब परिणाम आया तो मुश्किल से तीन सीटों पर ही पार्टी जीत हासिल कर सकी। जब उन्होंने इसका कारण जानने के लिए सभी 13 संसदीय सीटों के नेताओं आदि से बात की, तो पता चला कि महिलाओं को एक हजार रुपये महीना देने का जो वादा पार्टी ने किया था, उसे पूरा नहीं करने के चलते हार हुई।

साफ है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट बांट कर वोट हासिल करना अगले चुनाव में जीत की गारंटी नहीं होती। मुफ्त बिजली, मुफ्त इलाज को भूलकर जनता को केवल वह बात याद रही जो उन्हें नहीं मिला। जो मिल गया, उसे वे भूल गए। उपरोक्त चर्चा का सार केवल इतना है कि सब्सिडी चुनाव में जीत की गारंटी नहीं है, लेकिन इससे राज्य की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल होने की पूरी गारंटी है। राज्य सरकार ने जिस प्रकार से दस हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त कर्ज लेने के लिए केंद्र को लिखा है, उससे साफ है कि 30 हजार करोड़ रुपये के मौजूदा कर्ज की सीमा भी पंजाब की आर्थिकी को पटरी पर बनाए रखने के लिए काफी साबित नहीं हो रही है। दस साल पहले तक पंजाब पर सिर्फ एक लाख करोड़ रुपये तक का कर्ज था, जो बढ़कर चालू वित्त वर्ष के अंत तक साढ़े तीन लाख करोड़ हो गया है और इसके आगे भी घटने की कोई संभावना नहीं है।

इसका सीधा असर अब विकास कार्यों पर दिखाई देने लगा है। पंजाब में पूंजीगत खर्च लगातार कम होता जा रहा है। नई भर्ती करने में वित्त विभाग ना-नुकर करने लगा है। जीएसटी के कारण नए कर लगाने की संभावनाएं भी खत्म होती जा रही हैं। सीमावर्ती प्रांत होने के कारण बड़ा निवेश पंजाब में नहीं आ रहा है। ऐसे में न तो राजस्व बढ़ने की ज्यादा संभावना है और न ही खर्च कम करने की, तो किस प्रकार आर्थिकी को पटरी पर लाया जा सकेगा। उसका एक बड़ा समाधान सब्सिडी को तर्कसंगत करना है। लेकिन यह ऐसी घंटी है जिसे बिल्ली के गले में बांधने को कोई भी पार्टी या नेता तैयार नहीं है। वर्ष 2022 में आम आदमी पार्टी को पंजाब की जनता ने ऐसा करने का मौका दिया था, लेकिन पार्टी ने वह गंवा दिया है। अब आधा कार्यकाल बीतने के बाद वह कोई बड़ा कदम उठा पाएंगे, इसकी संभावनाएं बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं।

जागरण जनमत कल का परिणाम

ओटीटी पर दिखाई जाने वाली सामग्री के लिए भी सेंसर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए?

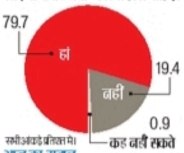

सभी आंकड़े प्रतिशत में।

आज का सवाल

क्या अमेरिका में राहुल गांधी के बयान कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।

जनपथ

साजिश करने में लगे पलटाने को ट्रेन,
बुरे काम में ही लगे 'शांतिदूत' का ब्रेन।
'शांतिदूत' का ब्रेन चाहता आग लगाना,
हो सौ-दो सौ मौत यही है शायद ठाना।
लिये हाथ पेट्रोल और पाकेट में माचिस,
लगे हुए हैं रोज मियां करने में साजिश।
- ओमप्रकाश तिवारी

मंथन

रवि नितेश
पर्यावरण मामलों के जानकार

शहरी वायु प्रदूषण संकट

देश के शहरी क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण संकट पर फिर से चिंता जताई गई है। लिहाजा इस समस्या के समाधान की दिशा में समन्वित प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

मानसून के बाद ठंड आने की आहट के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण की चर्चा एक बार फिर होने लगी है। पक्ष-विपक्ष अपनी अपनी तरह से इस विषय पर आवाज उठा रहे हैं। लेकिन इस महत्वपूर्ण विषय पर जिसमें हर एक व्यक्ति का प्रभावित होना निश्चित है, और यह समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, इस पर संयुक्त विमर्श दिखाई नहीं पड़ता। वस्तुतः हमारे शहर जीवंत और चहल-पहल वाले केंद्र के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन अब ये वायु प्रदूषण के खतरे से जूझ रहे हैं जिससे यहां सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न हो रहा है। समस्या का पैमाना चिंताजनक है, जिसमें कई भारतीय शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हैं और इन सबके बावजूद सामाजिक, राजनीतिक उदासीनता इतनी है कि चुनावों में पर्यावरण या साफ हवा कोई विशेष मुद्दा नहीं बन पाता है।

भारत के शहरी वायु प्रदूषण संकट के पीछे अनेक कारकों का आपस में एक जटिल संबंध है। वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण कार्यों से निकलते धूल और अन्य पदार्थों के कण एवं कृषि अपशिष्टों को जलाना, ये सभी हवा में मौजूद जहरीले मिश्रण में योगदान करते हैं। सड़कों पर कारों, बसों और दोपहिया वाहनों की बढ़ती संख्या ने पार्टिकुलेट मैटर और हानिकारक गैसों में बढ़ोत्तरी की है। औद्योगिक उत्सर्जन, विशेष रूप से बिजली संयंत्रों, स्टील मिलों और रिफाइनरियों से होने वाला उत्सर्जन की भी, प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इंडिया क्लीन एयर समिट के एक हालिया अधिवेशन में बताया गया कि शहरी प्रदूषण को प्रभावित करने वाले बहुत से कारक महानगरों के किनारे पर बसे अन्य छोटे शहर और अर्धशहरी क्षेत्र में भी हैं। इसलिए केवल किसी शहर विशेष के नगरीय निकाय अकेले ही शहरी प्रदूषण की रोकथाम नहीं कर सकते, लिहाजा इसके लिए समेकित नीति बनाने की आवश्यकता है।

सेंटर फार रिसर्च आन एनर्जी एंड क्लीन एयर की 2024 की पहली छमाही की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली भारत का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा, जहां पीएम 2.5 की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित मानक से 20 गुना अधिक पाई गई। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में तीन हरियाणा, दो राजस्थान, दो उत्तर प्रदेश एवं दिल्ली, जबकि असम और बिहार के एक-एक शहर शामिल हैं।

वायु प्रदूषण के रोकथाम की सबसे महती आवश्यकता इसके विनाशकारी स्वास्थ्य परिणामों के कारण है। प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से कई तरह की बीमारियां होती हैं, जिनमें श्वसन संक्रमण, हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और समय से पहले मृत्यु शामिल हैं। वायु प्रदूषण के प्रभावों के प्रति बच्चे विशेष रूप से संवेदनशील होते हैं और उनके संज्ञानात्मक विकास और फेफड़ों की कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है।

हालांकि वायु प्रदूषण संकट की गंभीरता को समझते हुए, भारत सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए कई पहलों को लागू किया है। इनमें राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शामिल है, जिसका उद्देश्य शहरों में पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण कम करना है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन, प्राकृतिक गैस और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दिया है। प्रभावी वायु प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लागू करने में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, आर्थिक विकास और ऊर्जा की बढ़ती मांग ने बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर दबाव डाला है। इसके अलावा, अनौपचारिक आर्थिक संरचना में प्रदूषण के कारकों को अक्सर विनियमित करना मुश्किल होता है।

ठंड के मौसम में वायु प्रदूषण बढ़ने से उसके दुष्प्रभावों को कम करने की तैयारी की जा रही है। फाइल

बहुआयामी दृष्टिकोण : भारत के शहरी वायु प्रदूषण संकट से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। पर्यावरण मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकारी नीतियों और नियमों को मजबूत किया जाना एवं निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक परिवहन और बुनियादी ढांचे में निवेश आवश्यक है। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने से औद्योगिक उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी। नागरिकों को स्वच्छ हवा की मांग करने और सरकारों को जवाबदेह ठहराने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

समुदाय-आधारित सुझावों को स्थानीय स्तर पर प्रदूषण कम करने में विचार-विमर्श का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। स्कूलों, कालेजों और कार्यालयों के समय में अंतर किया जाना, बैटरी आधारित ई-रिक्शा को विनियमित किया जाना, एक प्रकार के कार्य करने वाले कार्यालयों को एक तरह की टाइमिंग और फ्लेक्सी टाइमिंग के लिए बढ़ावा दिया जाना, कुछ निश्चित संख्या से अधिक लोगों का एक स्थान पर कार्य किए जाने पर कर्मचारी बसों की सुविधा बढ़ाया जाना आदि विचारों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रदूषण की रोकथाम के लिए किसी एक सरकार या विभाग या मंत्रालय नहीं, बल्कि सबको मिलकर काम करना ही प्रभावी हो सकता है।

****

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 11 सितंबर 2024

BJP विरोधी वोट बंटेंगे?

हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए विपक्षी I.N.D.I.A. ब्लॉक में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच गठबंधन की बातचीत टूटने के बाद AAP ने प्रत्याशियों की दो-दो सूची जारी कर दी है, सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का एलान भी कर दिया है। फिर भी दोनों दलों में कुछ लोग हैं, जो अभी गठबंधन की उम्मीद छोड़ने को तैयार नहीं हैं।

प्रदेश कांग्रेस का मूड | यह बात पहले दिन से साफ है कि हरियाणा कांग्रेस इस बार किसी से भी गठबंधन करने के पक्ष में नहीं है। प्रदेश कांग्रेस नेताओं के मुताबिक, दस वर्षों की एंटी इनकंबेंसी के मद्देनजर BJP 2019 से कमजोर स्थिति में है, जब उसे 90 सीटों की विधानसभा में 40 सीटें मिली थीं। हालिया लोकसभा चुनावों के नतीजे भी संकेत दे रहे हैं जहां पिछली बार की दसों सीटों की जगह उसे सिर्फ 5 सीटें मिलीं। AAP को कांग्रेस के साथ गठबंधन में यहां एक लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का मौका मिला था, लेकिन वह हार गई थी। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस गठबंधन को पूरी तरह गैर जरूरी मान रहा है।

AAP और कांग्रेस आमने-सामने

राष्ट्रीय नेतृत्व का आग्रह | अगर दोनों पक्ष गठबंधन के लिए बातचीत की मेज पर बैठे तो उसके पीछे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व का आग्रह था। राहुल गांधी अब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और उनकी प्राथमिकता यह है कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष के I.N.D.I.A. ब्लॉक की एकजुटता और उसकी मजबूती में किसी तरह की कमी न दिखे ताकि केंद्र सरकार और BJP पर उसका दबाव बना रहे।

चुनाव की अहमियत | हालिया लोकसभा चुनाव में BJP की सीटों में आई कमी के बाद विपक्ष को जो थोड़ी धार मिली है, उसके मद्देनजर ये चुनाव अहम माने जा रहे हैं। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं। दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी ज्यादा दूर नहीं हैं। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव में अगर I.N.D.I.A. ब्लॉक साथ मिलकर मजबूती से लड़ता दिखा और अच्छी जीत दर्ज करा पाया तो उसका असर न केवल आने वाले विधानसभा चुनावों पर बल्कि पूरे विपक्ष के मनोबल पर पड़ेगा।

वोट बंटने के नुकसान | मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों को याद करें तो इस पर लगभग आम राय है कि वहां कांग्रेस को प्रदेश नेतृत्व के अति आत्मविश्वास का नुकसान हुआ। जाहिर है, कांग्रेस इस बार ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी। असल सवाल विपक्षी वोटों के बंटवारे का है। जिस तरह से AAP प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही है, उससे साफ है कि वह इसी पहलू की ओर इशारा कर रही है कि उसे सीटें भले न आएं, कांग्रेस को कई सीटों का नुकसान तो हो ही सकता है।

इन दिनों

ट्रंप को बाइडन का रोग

मृत्युंजय राय

राजनीति में हफ्ते भर का वक्त भी काफी होता है और कुछ महीनों की तो बात ही क्या कहें। अमेरिका में नवंबर में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनावों से पहले ऐसा ही हो रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडन के अधिक उम्र की वजह से चुनाव से पीछे हटने और कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनने के बाद वहां राजनीतिक समीकरण तेजी से बदले हैं। पहली बात तो यही है कि जिस अधिक उम्र के मुद्दे की वजह से बाइडन को पीछे हटना पड़ा, वही अब रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के गले से आ लिपटा है। ट्रंप की उम्र अभी 78 साल है और वह अब तक अमेरिका की दोनों प्रमुख पार्टियों की ओर से राष्ट्रपति चुनाव लड़ने वाले सबसे अधिक उम्र के प्रत्याशी हैं। अगर ट्रंप जीते तो चार साल का कार्यकाल खत्म होने पर उनकी उम्र 82 वर्ष होगी। वह तब अमेरिकी इतिहास के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति होंगे, वहीं कमला हैरिस की उम्र अभी 59 साल है।

यही नहीं, बाइडन की भूलने की आदत के ट्रंप भी शिकार हैं। उनकी तरह ही ट्रंप की कही कुछ बातों का सिर-पैर नहीं निकला। हाल ही में जब ट्रंप से 'चाइल्ड केयर' के महंगा होने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया, जिसका कोई अर्थ नहीं था। ट्रंप के लिए बुरी बात यह हुई कि इसका विडियो वायरल भी हो गया। निक्की हेली और नैंसी पेलोसी में ट्रंप गफलत का शिकार हो चुके हैं। उन्होंने एक से अधिक बार यह भी कहा है कि वह बराक ओबामा को हराकर राष्ट्रपति बने थे, जबकि चुनाव में उन्होंने हेलरी क्लिंटन को हराया था। इन हालत में उन्हें खुद के मेंटली फिट होने का बचाव करना पड़ रहा है। हालांकि, इसके लिए भी जब ट्रंप ने दलील दी तो अपने डॉक्टर का सही नाम नहीं बता पाए।

फिर अक्सर वह ऐसी बात कह देते हैं, जिसका बचाव करना उनके समर्थकों के लिए भी मुश्किल हो जाता है। आने वाले वक्त में इसे लेकर ट्रंप पर और सवाल उठेंगे। लेकिन इस मामले में उनके एक कैंपेन मैनेजर ने कहा कि ट्रंप में जो ऊर्जा है, उसका मुकाबला कोई और राजनेता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वही मजबूत प्रत्याशी हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने अपने बेमतलब के बयानों का बचाव नहीं किया। उन्होंने हाल ही में कहा था कि वह भले ही 9 अलग-अलग मुद्दों की बात करें, लेकिन आखिर में वे सब मिलकर एक अर्थ लोगों के सामने पेश करेंगे। ट्रंप ने कहा कि यह उनके भाषण देने की खास शैली है। आज देर रात उनकी कमला हैरिस के साथ लाइव डिबेट हो रही है। इसमें लोगों की नजर इस बात पर भी होगी कि बाइडन का रोग कहीं ट्रंप को भी तो नहीं लग गया है।

एकदा

तुकाराम का पेड़

17वीं सदी में महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत और कवि हुए तुकाराम। उनका जन्म एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। उनके गांव का नाम था देहू। उस गांव में पीपल का एक बड़ा पेड़ था। गांव के लोग मानते थे कि उस पेड़ के नीचे से गुजरना अशुभ होता है और जो उस पेड़ के नीचे से गुजरेगा उसके जीवन पर नकारात्मक असर पड़ेगा। तुकाराम को गांव वालों की यह बात अच्छी नहीं लगती। वह कहते थे कि पूरी प्रकृति ईश्वर की बनाई हुई है। इसके कण-कण में ईश्वर का वास है, फिर चाहे मनुष्य, पशु-पक्षी या पेड़-पौधे ही क्यों न हों। अब उन्होंने गांव वालों के इस डर और भ्रम को दूर करने की ठानी। पहले उन्होंने उस पेड़ के नीचे अपना कुछ समय बिताया।

Subrata Dhar

फिर एक दिन उन्होंने गांव वालों को वहां बुलाया और समझाया कि यह अंधविश्वास है। उन्होंने कहा कि वृक्ष हमें जीवन प्रदान करते हैं, न कि हमारा नुकसान करते हैं। पेड़ हमारे अच्छे मित्र होते हैं। यह अंधविश्वास केवल आप लोगों को डराने और आपका मनोबल कम करने के लिए फैलाया गया है। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। उन्होंने कहा कि आज से हम सब मिलकर इस पेड़ के नीचे से गुजरेंगे और दिखाएंगे कि इसका कोई बुरा असर नहीं होता है। तुकाराम के पेड़ के नीचे समय बिताने और उनकी बातों से गांव वालों को भरोसा हुआ। गांव वाले भी पेड़ के नीचे से गुजरने लगे। आते-जाते लोग पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तो डर और अंधविश्वास से छुटकारा मिल गया। संत तुकाराम का मानना था कि मनुष्य को तर्कशील बनना चाहिए और सच्चाई तक पहुंचने के लिए अंधविश्वास का त्याग करना चाहिए।

संकलन : रिंकल शर्मा

कश्मीर की प्रमुख पार्टियां संसद हमले के दोषी अफ़ज़ल गुरु को फांसी पर भी उठा रही हैं सवाल

चुनावी मुद्दों से मिल रहे हैं कैसे संकेत

अवधेश कुमार

अगर जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव में उठाए जा रहे मुद्दों पर गौर करें तो कुछ चिंताजनक संकेत दिख रहे हैं। लंबे समय से वहां की राजनीति में स्थापित प्रमुख पार्टियां नैशनल कॉन्फ्रेंस और PDP व हाल में खड़ी हुई जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के कई मुद्दे देश की एकता-अखंडता और वहां की शांति व्यवस्था की दृष्टि से खतरनाक हो सकते हैं।

फांसी पर सवाल | नैशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने अब संसद हमले के अभियुक्त अफजल गुरु की फांसी को भी चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने कहा है कि अफजल गुरु की फांसी में जम्मू-कश्मीर सरकार की मंजूरी की जरूरत पड़ती तो हम नहीं देते। उन्होंने यह भी कहा कि 'मुझे नहीं लगता उसे फांसी देने से कोई उद्देश्य पूरा हुआ है। हमने कई बार देखा है कि फांसी की सजा दे दी जाती है और बाद में पता चलता है कि व्यक्ति निर्दोष था।'

जमात की तरफदारी | दरअसल, अफजल गुरु के भाई एजाज अहमद गुरु के विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा करते ही पार्टियों ने यह राग अलापना शुरू कर दिया। महबूबा मुफ्ती अफजल गुरु की फांसी को अन्याय बताती रही हैं। उनकी प्रतिक्रिया भी यही है। यही नहीं, उन्होंने जमात-ए-इस्लामी से प्रतिबंध हटाकर उसे चुनाव लड़ने की इजाजत देने की भी मांग की है। मौजूदा जानकारी के मुताबिक, प्रतिबंधित जमात-ए-इस्लामी के सदस्य निर्दलीय नामांकन भर रहे हैं।

370 की वापसी का वादा | ये पार्टियां अनुच्छेद 370 की बहाली के साथ ही जम्मू-कश्मीर को स्वायत्त और अनेक मामलों में स्वतंत्र अवस्था में लाने का वादा कर रही हैं। नैशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणापत्र में शंकराचार्य पर्वत को तख्त-ए-सुलेमान और हरी पर्वत को कोहे मारन नाम देने की घोषणा भी है। नैशनल कॉन्फ्रेंस की चर्चा इसलिए कि देश में ऐसी छवि बनाई गई कि यह पार्टी और अब्दुल्ला परिवार अन्य नेताओं के मुकाबले ज्यादा लिबरल और भारत समर्थक है।

विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और नैशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है

आजमाए सारे विकल्प | अफजल गुरु 13 दिसंबर, 2001 को संसद पर हमले के दो दिन बाद 15 दिसंबर को गिरफ्तार हुआ था। 18 दिसंबर, 2002 को अफजल गुरु, एसआर गिलानी और शौकत हसन गुरु को फांसी की सजा दी गई तथा एक आरोपी अहसान गुरु को बरी किया गया। 4 अगस्त, 2005 को उच्चतम न्यायालय ने अफजल गुरु की सजा को बरकरार रखा और शौकत हसन गुरु की फांसी की सजा को 10 साल के कठोर कारावास में बदल दिया।

अलगाववाद पर जोर
- जमात से बैन हटाने की हो रही मांग
- 370 की वापसी का कर रहे हैं वादा
- कांग्रेस की चुप्पी हैरान करने वाली

फिजूल का मुद्दा | अफजल गुरु की ओर से सुप्रीम कोर्ट में डाली गई दया याचिका 12 जनवरी, 2007 को खारिज हो गई। 23 जनवरी, 2013 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने भी इसे खारिज कर दिया। तब 9 फरवरी, 2013 को तिहाड़ जेल में सुबह अफजल को फांसी दी गई। ध्यान में रहे कि अफजल को न्यायिक प्रक्रिया के सारे विकल्प उपलब्ध रहे।

कांग्रेस की चुप्पी | उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री थे जब विधानसभा में चर्चा के दौरान अफजल को निर्दोष कहा गया और फांसी के विरुद्ध प्रस्ताव पारित हुआ। इस बार कांग्रेस का नैशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनावी गठजोड़ है। कांग्रेस के ही शासनकाल में फांसी की सजा पर अमल हुआ था, पर वह इसके विरुद्ध वक्तव्य देने से बच रही है। कांग्रेस ने नैशनल कॉन्फ्रेंस की उन घोषणाओं का भी विरोध नहीं किया जो इस्लामी कट्टरवाद और अलगाववाद को उभारने की कोशिश लग रही हैं।

आंतरिक संरचना में बदलाव | कश्मीर में पाकिस्तान या आजादी समर्थकों का मूल तर्क यही रहा है कि मुस्लिम बहुल होने के कारण जम्मू-कश्मीर की अलग पहचान है और उसी रूप में इसका अस्तित्व बने रहना चाहिए। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद कश्मीर में विधायी व प्रशासनिक से लेकर आंतरिक राजनीतिक संरचना आदि में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। इसका असर वहां की अर्थव्यवस्था, लोगों के जनजीवन पर अत्यंत सकारात्मक हुआ है। इसमें आम आदमी सोचने लगा है कि क्या अभी तक हमें गफलत में रखा गया?

विरोध होना चाहिए | इन पार्टियों की सोच यह लगती है कि कश्मीर की स्वायत्तता बड़े वर्ग के अंदर पुराने दौर की ओर लौटने की भावना को मजबूत करेगी, जिसका उन्हें चुनावी लाभ मिलेगा। साफ है, मजहबी अलगाववाद, आतंकवाद और पाकिस्तान को अब भी ये पार्टियां अपनी राजनीतिक हैसियत के लिए जरूरी मानती हैं। चुनाव में पार्टियों का राजनीतिक स्वार्थ होता ही है किंतु देश की दृष्टि से इस तरह के विचार और व्यवहार का सभी पार्टियों, नेताओं और बुद्धिजीवियों को एक स्वर में विरोध करना चाहिए।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और विचारक हैं)

सोना है हर आपदा के लिए...

● खरीदार ● दुकानदार

दुनिया भर के सेंट्रल बैंक इस साल बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। सोना फिर से एक महत्वपूर्ण एसेट के रूप में उभर रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार, सिर्फ जुलाई 2024 में ही 37 टन सोना खरीदा गया। रूस-यूक्रेन युद्ध, गजा-इस्राइल युद्ध और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के चलते कई देश अपनी संपत्ति के भंडार को सुरक्षित बनाने के लिए सोने पर जोर दे रहे हैं। जानते हैं इस पूरे कारोबार के बारे में...

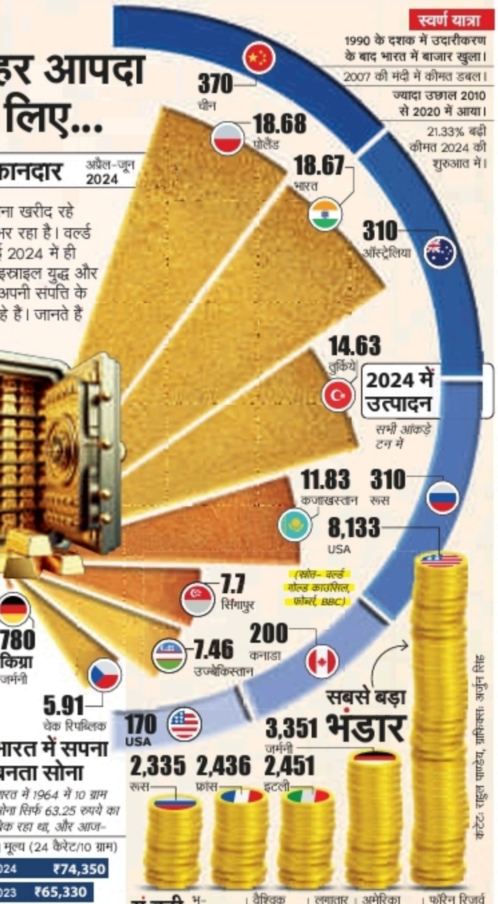

दमकता सोना

183 टन सोना खरीदा गया 2024 की दूसरी तिमाही में।

2023 की समान अवधि में 173.6 टन सोना खरीदा गया था।	पोलैंड सबसे आगे रहा, 18.68 टन सोना खरीदते हुए।
भारत ने 2024 की दूसरी तिमाही में 18.67 टन सोना खरीदा।	2023 में केंद्रीय बैंकों ने कुल 1,037 टन सोना अपने भंडार में जोड़ा।

846 टन पहुंचा भारत का गोल्ड रिजर्व।
2016 के बाद 2024 में हो रही बड़ी खरीद।

चीन का गोल्ड रिजर्व 2,250 टन के पार हुआ।

क्यों खरीदते हैं सोना

रिजर्व एसेट *संकट के समय में स्थिरता लाता है।*
- डॉलर पर निर्भरता कम करना।
- मुद्रा विविधता लाने में मदद करता है।
- संकट के समय में सुरक्षित संपत्ति।
- देश दिवालिया होने से बच जाते हैं।

नुकसान
- लिक्विडिटी कम होती है।
- तुरंत बेचने में दिक्कत।
- ब्याज न मिलने का जोखिम।
- कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव।

भारत का खजाना

- RBI ने 2024 की पहली तिमाही में 19 टन सोना खरीदा।
- यह 2023 में पूरे साल में खरीदे गए 16 टन सोने से ज्यादा।
- मई 2024 में भारत सोने का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार।
- मार्च 2019 में देश का गोल्ड रिजर्व 618.2 टन।
- 31 मार्च 2024 तक 33% बढ़ा गोल्ड रिजर्व।

भारत में सपना बनता सोना

भारत में 1964 में 10 ग्राम सोना सिर्फ 63.25 रुपये का बिक रहा था, और आज-

वर्ष	मूल्य (24 कैरेट/10 ग्राम)
2024	₹74,350
2023	₹65,330
2022	₹52,670
2021	₹48,720
2020	₹48,651

यूं बढ़ी खरीद

भू-राजनीतिक तनाव से सुरक्षा।	वैश्विक मंदी की आशंका भी है वजह।	लगातार डगमगा रहा है डॉलर।	अमेरिका के साथ बिगड़ते देशों के रिश्ते।	फॉरेन रिजर्व को मजबूत करने का प्रयास।

मुद्रास्फीति के खिलाफ भी सबसे कारगर हथियार।

क्या चुनाव से ख़त्म होगी श्रीलंका की मुश्किल

कल्लोल चक्रवर्ती

लगभग 2.3 करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका के करीब 1.7 करोड़ मतदाता 21 सितंबर को वोट डालेंगे। 2022 के आर्थिक संकट और जन आंदोलन (अरगलया) के बाद वहां यह पहला चुनाव है। दो साल पहले पैदा हुए हालात में तत्कालीन राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को इस्तीफा देना पड़ा था। तब संसद ने उनके बचे हुए कार्यकाल के लिए रानिल विक्रमसिंघे को राष्ट्रपति चुना था।

परेशानी में जनता | श्रीलंका को पिछले साल IMF से 2.9 अरब डॉलर की मदद मिली थी। मुद्रास्फीति भी सितंबर 2022 के 70% से घटकर विगत जून में एक अंक में आ गई। ब्याज दर घटी है और विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा है। लेकिन, समस्याएं अब भी हैं।

महंगाई से परेशानी | व्यापारी टैक्स की बढ़ी दर से परेशान हैं। जीवनयापन महंगा हो गया है। विश्व बैंक के मुताबिक, श्रीलंका में लगभग 26% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। भोजन, ईंधन और दवा के लिए जनता भले अब सड़कों पर नहीं उतर रही, लेकिन महंगाई से जीवन प्रभावित हो रहा है।

सबसे बड़ा मुद्दा | महंगाई और भ्रष्टाचार इस चुनाव में बड़े मुद्दे हैं। नस्लीय हिंसा के समाधान के लिए वर्ष 1987 में किया गया 13वां संविधान संशोधन भी एक बड़ा मुद्दा है, जो राजीव गांधी और जेआर जयवर्धने के बीच हुए समझौते का हिस्सा था। इस संविधान संशोधन के तहत गृहयुद्ध जैसी स्थिति खत्म करने के लिए श्रीलंका के सभी नौ राज्यों को कृषि, स्वास्थ्य, पुलिस आदि के अधिकार देना था। लेकिन, अभी तक इस पर अमल ही नहीं हुआ है।

संशोधन का पहलू | भारत इस संशोधन को लागू करने के बारे में कहता आया है, क्योंकि इससे तमिल बहुल प्रांतों को भी पुलिस और जमीन के अधिकार मिलेंगे। सिर्फ मुख्य विपक्षी पार्टी SJB के साजित प्रेमदासा ने ही, जो नेता विपक्ष भी हैं, चुनाव जीतने पर 13वें संशोधन को संपूर्णता में लागू करने का वादा किया है। विक्रमसिंघे ने पुलिस पावर के बगैर संशोधन को लागू करने का प्रस्ताव रखा है, जबकि दिसानायके ने तो संविधान ही बदल देने की बात कही है।

तमिल फैक्टर | इस बार तमिल समूहों ने अपना प्रत्याशी चुना था, लेकिन बाद में उन्होंने प्रेमदासा का समर्थन करने की बात कही। पिछले चुनाव में राजपक्षे के खिलाफ वोट देने वाला तमिल समुदाय इस बार ज्यादा संगठित नजर आ रहा है। उसकी कोशिश है कि कुल 22 लाख तमिल वोट इस बार बंटें नहीं।

कॉमन रूम

तीन उम्मीदवार | राष्ट्रपति पद के दो और उम्मीदवार हैं, निर्दलीय विक्रमसिंघे और वामपंथी जनता विमुक्ति पैरामुना के नेता अनुरा कुमारा दिसानायके। महिंदा राजपक्षे के बेटे नमाल भी चुनावी दौड़ में शामिल हैं। अनुरा दिसानायके चीन समर्थक तो हैं ही, उनकी पार्टी NPP में शामिल सिविल सोसाइटी और पर्यावरण समूह भी भारत विरोधी बताए जाते हैं। उनकी जीत से भारत के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी।

रानिल से असंतोष | विक्रमसिंघे ने मुश्किल समय में देश को स्थिरता प्रदान की। उन्हें भारत समर्थक माना जाता है और वैश्विक समर्थन भी उन्हें हासिल है। लेकिन, श्रीलंका के लोगों का मानना है कि रानिल ने भ्रष्ट राजपक्षे परिवार को संरक्षण दिया, जिसके बदले में उन्हें राष्ट्रपति पद मिला। भारी टैक्स लगाने, बिजली और दूसरी सेवाओं में मिलने वाली सब्सिडी खत्म कर देने और IMF के दिशा-निर्देशों के अनुरूप फिजूलखर्ची पर अंकुश लगाने के कारण भी रानिल अलोकप्रिय हो चुके हैं।

सबसे बड़ी आशंका | चुनाव में तीन उम्मीदवार होने से आशंका बनी है कि शायद पहली बार 50% से कम वोट पाने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाए। श्रीलंका में मतदाताओं को अपनी तीन वरीयताओं के बारे में बताना होता है। अगर पहली वरीयता वाले प्रत्याशी को 50% वोट नहीं मिले, तो दूसरी और तीसरी वरीयता वाले प्रत्याशियों के वोटों की गिनती करनी पड़ सकती है। चूंकि वहां पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं आई, तो 50% से कम वोट पाकर राष्ट्रपति बनने वाले नेता की वैधता पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। यानी चुनाव के बाद भी श्रीलंका में अस्थिरता रहे, तो आश्चर्य नहीं होगा।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

मन में चल रहीं बेकार की बातों को छोड़ दीजिए

ब्रह्मा कुमारी शिवानी

जीवन एक यज्ञ है। हवन कुंड में जब आहुति डालते हैं, तो स्वाहा करते हैं। उसी प्रकार जीवन रूपी यज्ञ कुंड में जब हम परमात्म ज्ञान रूपी घी डालें, तो ईश्वर के प्रति हमारी लगन की अगन (अग्नि) पैदा होगी। उसको ही योग की अग्नि कहते हैं, जिससे मनोविकार, विकर्म और पाप कर्म जलते हैं। जब हम सच्चे मन और लगन से रूहानी ज्ञान की बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं और मनन-चिंतन करते हैं और योग की अग्नि जलाते हैं, तो उस समय कोई भी ऐसा अशुभ संकल्प, पुरानी आदत, कोई पुरानी याद, किसी के बारे में गलत सोच, या किसी को क्षमा नहीं करने का दर्द वगैरह जो हमारे पास रखने योग्य नहीं है, वे सब बातें अंदर से धीरे-धीरे स्वाहा हो जाती हैं।

बुराइयों या अवगुणों को ऊपर-ऊपर से आहुति देने से, या सिर्फ मुख से प्रभु अर्पण करने से वे समाप्त नहीं होते। सच्चे हवन का मतलब है हमारे अंदर की दूषित चीजों, कमजोरियों और दुख-दर्द वाली सोच को हम स्वाहा कर दें। तभी हम अपने अंदर सही बदलाव ला सकते हैं। दूसरा, हवन कुंड के ऊपर स्वास्तिक चिह्न लगाते हैं। स्वास्तिक यानी स्व का और अंतरात्मा का अस्तित्व। स्वास्तिक के चार भाग होते हैं। इसका पहला भाग दाएं की ओर होता है, यानी हाथ देने की मुद्रा में होता है। जैसे कि हाथ से हम औरों को दुआएं या वरदान देते हैं। इसे सृष्टि की सुबह, आदिकाल या सतयुग कहते हैं। जैसे हर दिन सुबह, दोपहर, शाम और रात होते हैं, वैसे ही स्वास्तिक का एक काल चक्र है। इसमें सृष्टि की सुबह, दोपहर, शाम और रात को दर्शाया गया है। सतयुग के बाद, स्वास्तिक का अगला भाग पूर्व से दक्षिण यानी नीचे की ओर घूमता है। यह त्रेता युग को इंगित करता है। इसमें देने का संस्कार है, पर सतयुग की तुलना में इस युग में थोड़ा कम हो जाता है।

फिर, स्वास्तिक की दिशा बाएं तरफ यानी पश्चिम की ओर मुड़ती है, और द्वापर युग में पहुंचती है। इस काल में हमारे अंदर की दिव्यता और पवित्रता कम हो जाती है। इस युग में हमारे हाथ देने की मुद्रा से मांगने की अवस्था में आ जाते हैं यानी व्यक्ति औरों से स्नेह, शक्ति, संपत्ति और आदर-सम्मान आदि चाहने लगता है। स्वास्तिक का हाथ जब ऊपर की ओर मुड़ता है, तो हम चौथे युग कलयुग में पहुंच जाते हैं। हमारे हाथ देने और मांगने की स्थिति से मारने की मुद्रा में आ जाते हैं। इस युग में हम सारा दिन खुद को मारते हैं- मन से, अपनी सोच से, over thinking से या non-stop सोच से। कोई व्यक्ति एक लाइन बोल के चला जाता है, हम अपने को हजार लाइन बोलना शुरू कर देते हैं। फिर कहते हैं कि उसने हमें दुख दिया। पर उसने तो सिर्फ एक लाइन बोली थी। उसके बाद मुझे किसने मारा? मुझे मेरे अंदर लगातार चल रही व्यर्थ सोच ने मारा।

दुख देने वाली सोच और स्वभाव चाहे अपने लिए हो या दूसरों के प्रति, उसे परमात्म ज्ञान और योग रूपी हवन कुंड में स्वाहा करना है। कोई कैसा भी बोल बोले और व्यवहार करे, हमें उसे दुआएं देनी हैं, उसके प्रति दया, करुणा, शुभ भावना और शुभ कामना रखनी है। जैसे ही हम औरों को दुआएं देने लगेंगे, सुख देने वाली सोच, वृत्ति और संस्कार बनाएंगे, तो धीरे-धीरे हमारे अंदर और बाहर सुखदाई वातावरण और सुखमय संसार बनता जाएगा।

राष्ट्रीय
सहारा
पटना • बुधवार • 11 सितम्बर • 2024
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

ज्यादातर लोग वास्तव में स्वतंत्रता नहीं चाहते, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी आ जाती है, और ज्यादातर लोग जिम्मेदारी से डरते हैं
-सिगमंड फ्रायड

कठघरे में ममता

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद जवाहर सरकार का पार्टी और राज्य सभा की सदस्यता से त्यागपत्र देने का साफ संदेश है कि कोलकाता के आर.जी. कर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ हुए कथित दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले को ममता की सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया। लोकतंत्र 'जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए' शासन कहा जाता है। लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आमतौर पर भारत की लोकतांत्रिक सरकारें जनता की आवाज को अनसुना कर देती है। राज्य की शक्तियों का इस्तेमाल जनता की आवाज को कुचलना और दबाने के लिए किया जाता है। पश्चिम बंगाल के

इस संवेदनशील मामले में भी ऐसा ही देखा गया और इसी का परिणाम है कि सरकार की नाकामियों के विरुद्ध डॉक्टर और आमजनों का आंदोलन व्यापक होता जा रहा है। लोगों को याद होगा कि 75 के बिहार छात्र आंदोलन की आवाज को भी राज्य और केंद्र की सरकार ने पुलिस के बल पर दबाने की कोशिश की थी। परिणाम यह हुआ कि तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपने जीवन का सबसे सर्वनाकर का सामना करना पड़ा था। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पूर्ववर्ती वाममोर्चा की सरकार पर भी जनता की आवाज को दबाने का आरोप लगाया करती थीं। सत्ता में आने के बाद वह खुद इसी तरह का आचरण कर रही हैं। इसमें हैरानी की बात भी नहीं है क्योंकि इस तरह की चिताओं का सत्ताओं का यही चरित्र होता है। ममता बनर्जी इस जन आक्रोश को केंद्र सरकार और वामपंथी पार्टियों की साजिश बता रही हैं जबकि सरकार प्रशिक्षु डॉक्टर के मामले पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को स्वतः स्फूर्त बता रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार के खिलाफ ऐसा गुस्सा और अविश्वास कभी नहीं देखा है। सरकार की छवि ईमानदार नौकरशाह की रही है। वह केंद्र की भाजपा की नीतियों से क्षुब्ध होकर टीएमसी में शामिल हुए हैं। अब उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। जाहिर है ऐसे ईमानदार व्यक्ति के पद त्याग का मतलब है कि टीएमसी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रशिक्षु डॉक्टर से की गई हैवानियत की केस दर्ज करने में पुलिस द्वारा की गई 14 घंटे की देरी पर सवाल उठाया और पोस्टमार्टम के लिए आवश्यक कागजात नहीं होने पर चिंता जताई है। देखना है कि जुझारू नेता रहीं ममता इन मुश्किलों का सामना कैसे कर पाती हैं?

अधर में नौकरी

उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य में 69,000 सहायक शिक्षकों की नई चयन सूची तैयार करने के हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। जून 2020 व जनवरी में जारी शिक्षकों की चयन सूचियों को रद्द करने संबंधी हाई कोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसमें 6,800 अभ्यर्थी शामिल थे। एक याचिका के आधार पर अदालत ने राज्य सरकार व उप्र बेसिक शिक्षा बोर्ड के सचिव समेत अन्य को नोटिस भी जारी किया। हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को इन सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नई सूची तैयार करने का भी निर्देश दिया था। जनवरी 2019 में हुई सहायक शिक्षकों की परीक्षा में 4.10 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। जिसमें उत्तीर्ण हुए अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग का कटऑफ 67.11 फीसद व

ओबीसी का कटऑफ 66.73 फीसद रहा। मई 2020 में आरक्षण के नियमों का पालन न करने के आरोप में हाई कोर्ट में याचिका डाली गई। 2023 में सिंगल बेंच ने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है, उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। जिस पर पुनः अपील की गई। अगस्त 2024 में डबल बेंच ने उस फैसले को रद्द करते हुए, आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का आदेश दिया। इस नियुक्ति के विवाद को लेकर उनमें जबरदस्त आक्रोश है। नौकरी के इंतजार में भटकने वालों को छठे साल भी पदभार न मिलना, उनके भविष्य से खिलवाड़ है। सरकार पर मुसलसल दबाव पड़ रहा है। वह मान रही है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण का लाभ उचित अभ्यर्थियों को अवश्य प्राप्त होना चाहिए। इसके बावजूद यह कोताही किस स्तर पर हुई और इसका मकसद क्या था, यह भी जानना जरूरी है। नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने के बावजूद ये चयनीत सहायक शिक्षक इतने लंबे इंतजार से आजिज आ चुके हैं। चूंकि नियमानुसार राज्य सरकारें सरकारी नौकरियों में वर्टिकल कोटा तय करती हैं। उसमें किसी तरह की धांधली की गई या लापरवाही हुई, उसे दुरुस्त करना और दोषियों को सामने लाना भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। चयनित सदस्यों के साथ यह बड़ा अन्याय है। उनको होने वाली आर्थिक, मानसिक दिक्कतों के प्रति संवेदनशील रवैया रखना होगा। आखिर कब तक वे संशय में यूं दर-दर भटकते रहेंगे। समय रहते अगर सरकार युवाओं की दुश्वारियों को समझ लेगी तो यह हर किसी के लिए फायदेमंद रहेगा।

विचार/संजीव ठाकुर

मनोबल सफलता की कुंजी

अचानक मिलने वाली बड़ी सफलता एवं भारी असफलता आदमी पचा नहीं पाता है। सफलता तो फिर भी व्यक्ति खुशी से आत्मसात कर लेता है पर असफलता को झेलने के लिए आत्मविश्वास, मनोबल की परम आवश्यकता होती है। असफलता ऐसा स्वाद है जिसे हर व्यक्ति ने जीवन में कभी-न-कभी जरूर चखा होगा। असफल होने से निराश होने की आवश्यकता नहीं है।

महापुरुषों ने कहा है कि असफलता यह दर्शाती है कि आपने प्रयास पूरे मन से नहीं किया है। अतः असफलता के बाद सफलता के लक्ष्य को निर्धारित कर पूर्ण मनोयोग से कर्म की वेदी पर अपना शीश नवाना चाहिए। जीवन में असफलता किसी लक्ष्य को स्थापित करने का ही परिणाम है, इसीलिए इसे बड़े ही सहज तरीके से आत्मसात करना चाहिए। बिना असफलता के सफलता कोई भी स्वाद नहीं देती है। शायर फैज अहमद फैज ने कहा है-

दिल ना उम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है,
लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है।

युवाओं को सदैव लक्ष्य प्राप्ति और सफलता प्राप्ति के लिए निरंतर कठिन श्रम प्रयास संकल्प और अपनी जीवनी को नियमित रखना होगा जिससे घर, समाज और राष्ट्र की उन्नति भी होगी। उल्लेखनीय है की असफलता से ही सफलता की तमाम शिक्षा हमें प्राप्त होती है। विवेकानंद जी ने कहा है कि, ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हमारे ही भीतर ही है। यह हम ही हैं जिन्होंने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा है और रोते हुए कहते है कि अंधेरा है। मनुष्य के जीवन में आत्मविश्वास ही ऐसा गुण है जिससे हम संकल्पित होकर बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर जीवन में सफलता के झंडे गाड़ सकते हैं। यह देखा गया है कि मानव अहंकार को ही आत्मविश्वास समझने की भूल कर देते हैं। आत्मविश्वास अहंकार विहीन विनम्रता के साथ परिश्रम और संयम संकल्प लेकर सफलता के लक्ष्य की ओर पदार्पण ही है। फलस्वरूप अहंकार को त्याग कर संपूर्ण विश्वास को लेकर देश हित में सफलता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने चाहिए।

सामाजिक बदलाव का वाहक

जनधन खाता

सतीश सिंह

अट्ठाईस अगस्त 2014 को शुरू किए गए प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूरे हो गए। अपने 10 सालों के सफर के दौरान इस योजना ने कई उपलब्धियां हासिल की। यह योजना वित्तीय समावेशन की संकल्पना को साकार करने, महिला सशक्तीकरण को बढ़ाने, डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया को गांव-गांव व घर-घर तक पहुंचाने, ग्रामीण क्षेत्र में बिचौलिये व सूदखोरों या महाजनों की भूमिका को कम करने, चोरी-चकारी की घटनाओं में कमी लाने, भ्रष्टाचार कम करने, सामाजिक बदलाव लाने, जमा और खर्च आदि में तेजी को सुनिश्चित करने में सफल रहा है।

चालू वित्त वर्ष में 16 अगस्त तक इस योजना के तहत 3 करोड़ नए खाते खोले गए हैं। मार्च 2015 में जनधन खातों की संख्या 14.72 करोड़ थी, जो 16 अगस्त 2024 में बढ़कर 53.13 करोड़ हो गई, जो खाता खोलने के मामले लगभग 4 गुणा वृद्धि को दर्शाता है। खोले गए खातों में से 66.6 प्रतिशत खाते ग्रामीण और कस्बाई इलाकों में हैं। सबसे महत्त्वपूर्ण है कि 53.13 करोड़ खाते चालू या सक्रिय हैं और उनमें 2.3 लाख करोड़ रुपए का अधिशेष है, जबकि मार्च 2015 तक महज 14.7करोड़ खाते खोले जा सके थे और उनमें 15,670 करोड़ रुपए जमा थे। अगस्त 2024 में जनधन खातों में औसत अधिशेष 4,352 रुपए रहा, जो मार्च 2015 में 1,065 रुपए था। उल्लेखनीय है कि 16 अगस्त 2024 तक सिर्फ 8.4 प्रतिशत जनधन खातों में ही शून्य अधिशेष था। 53.13 करोड़ खातों में से 29.56 करोड़ खाते महिलाओं के हैं, जो प्रतिशत में 55.6 है।

जनधन खाता खोलने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सकारात्मक और महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकारी बैंकों ने कुल खोले गए जनधन खातों में से 78 प्रतिशत खाते खोले हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 9.4 करोड़ जनधन खाते खोले गए हैं, जबकि बिहार 6 करोड़ जनधन खाते खोलकर मामले में दूसरे स्थान पर है। जनधन खाते, मोबाइल और आधार कार्ड ने कोरोना महामारी में आमजन को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसान सम्मान निधि का वितरण छोटे एवं सीमांत किसानों के बीच करने में अहम भूमिका निभाई है। आज जनधन खातों की वजह से बसे हुए गांवों के 5 किलोमीटर के दायरे के 99.95 प्रतिशत लोगों की पहुंच बैंकिंग सुविधाओं तक हो गई है। गांव के लोग बैंक की शाखाओं, बैंकिंग कोरेस्पोंडेंट और भारतीय पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा उपलब्ध कराई गई बैंकिंग सुविधाओं का लाभ किसी न किसी रूप में ले रहे हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा शुरू किए गए फोन

आधारित गैर वित्तीय सेवाओं का लाभ भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोग बिना बैंक शाखा गए ले रहे हैं। जनधन खाता खोलने, खातों के रखरखाव और न्यूनतम अधिशेष राशि के नहीं रहने या खाता अधिशेष शून्य रहने पर भी बैंक द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जाता है और ग्राहकों को 10,000 रुपए तक ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी दी जा रही है। बैंक रुपे कार्ड भी निःशुल्क जारी कर रहे हैं, जिसके साथ ग्राहकों को 2 लाख रुपए तक का मुफ्त दुर्घटना बीमा भी दिया जा रहा है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना की वजह से आज 80 प्रतिशत वयस्क के पास औपचारिक बैंक खाता है, जबकि 2011 में यह प्रतिशत महज 50 थी। इस योजना ने वैश्विक स्तर पर वित्तीय समावेशन के संदर्भ में भारत का मान बढ़ाया है साथ ही इसके कारण परिवार की जगह व्यक्तिगत स्तर पर आमजन की पहुंच बैंक सुविधाओं तक हुई है। वित्तीय समावेशन के लिए समुचित परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए जरूरी है कि आमजन की भागीदारी के साथ-साथ सरकार की भी मामले में सक्रिय हिस्सेदारी हो। इस संदर्भ में सरकार और आमजन बढ़-चढ़ कर काम कर रहे हैं और निजी स्तर पर भी इसे बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। हालांकि, अभी भी जनधन खातों के साथ-साथ लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर करने और उन्हें ऑनलाइन धोखाधड़ी के खतरों से अवगत कराने की आवश्यकता है, जिसे निजी और सरकारी दोनों इकाइयों द्वारा लगातार किए जाने की जरूरत है, तभी प्रभावी तरीके से इन लक्ष्यों को हासिल किया जा सकता है।

जनधन खातों के कारण आज रुपे कार्ड ने ग्रामीणों की पहुंच दुनिया-जहान के बाजारों तक कर दी है। अब गांव के घरों में भी अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि देश-विदेश में बने उत्पादों की डिलिवरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जनधन खातों ने लोगों के बीच बचत करने की प्रवृत्ति विकसित की है साथ ही साथ खर्च करने की प्रवृत्ति में भी इजाफा किया है, जिसका मुख्य कारण ग्रामीणों की ऑनलाइन बाजार तक पहुंच होना है। इन बदलावों से आर्थिक गतिविधियों में भी तेजी आ रही है। जनधन खाते सामाजिक बदलाव के भी वाहक हैं। इनकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की घटनाओं में कमी आ रही है और लोगों की जुए खेलने और शराब पीने की लत में भी कमी देखी जा रही है। विगत दशक में डीबीटी के जरिये 38.49 लाख करोड़ रुपए अंतरित किए गए थे और 3.48 लाख करोड़ रुपए के लीकेज पर लगाम लगाया जा सका था, जो अमूमन जनधन खाते खोलने से पहले बिचौलिये एवं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे। जनधन खातों ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने, ई-कॉमर्स के कारोबार को बढ़ाने और यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम (यूपीआई) के जरिये डिजिटल भुगतान के मामले में दुनिया में भारत को शीर्ष पर पहुंचाने में भी मदद की है।

जुलाई 2024 तक भारत में यूपीआई के जरिये 5570 करोड़ लेनदेन किए गए थे। सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर और भी बेहतरी लाने के लिए जनधन खातों के साथ-साथ अब सरकार और बैंकों को ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु स्तर पर ऋण की सुविधा किफायती दर पर उपलब्ध कराने की भी जरूरत है, ताकि ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बन सके और ग्रामीण क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ सके। मौजूदा डिजिटलाइजेशन के दौर में यह भी जरूरी है कि शहरी व ग्रामीण आमजन को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उन्हें साक्षर करने की दिशा में निरंतर काम करते रहा जाए। सरकार को चाहिए कि वह जनधन खातों के साथ अन्य सरकारी योजनाओं को जोड़ने की व्यवस्था करे ताकि अधिक से अधिक संख्या में वंचित तबके को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।

(लेखक के निजी विचार हैं)

अब सरकार और बैंकों को ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु स्तर पर ऋण की सुविधा किफायती दर पर उपलब्ध कराने की भी जरूरत है, ताकि ग्रामीण भारत आत्मनिर्भर बन सके और ग्रामीण क्षेत्र का जीडीपी में हिस्सेदारी बढ़ सके। मौजूदा डिजिटलाइजेशन के दौर में यह भी जरूरी है कि शहरी व ग्रामीण आमजन को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने और उन्हें साक्षर करने की दिशा में निरंतर काम करते रहा जाए

पैदल चल कर सेहत की साज-संवार

- एक रिसर्च में दावा किया गया है कि हफ्ते में कम से कम तीन बार पांच हजार कदम से ज्यादा चलने वालों की जिंदगी खुशहाल और लंबी हो सकती है
- पदैल चलने से लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियां डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, मोटापा, डिप्रेशन आदि से भी बचा जा सकता है
- लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स के एक शोध से पता चला है दिन में एक हजार कदम चलना सेहत के लिहाज से बेस्ट माना गया है, लेकिन उम्र के हिसाब से हर किसी के लिए कदमों की संख्या अलग-अलग हो सकती है

(स्रोत : मीडिया इनपुट्स)

पाकिस्तान के बहादुर लोग। जलसे-वलसे से इमरान खान जेल से नहीं छूटेगा। तुम लोग अदियाला जेल पर हमला कर दो और उसे छुड़ा लाओ। यही एक तरीका है, अगर इसमें तुम शहीद हो गए तो जन्नत नसीब होगा 72 हूरों के साथ।

पूर्व जस्टिस मार्कण्डेय काटजू
@mkatju

सोच में आए बदलाव का नतीजा

पैरालंपिक में भारत | मनोज चतुर्वेदी

भारत अब पैरालंपिक खेलों में एक ताकत के रूप में उभर रहा है। उन्होंने पेरिस पैरालंपिक खेलों में सात स्वर्ण पदक सहित 29 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। अब यह कहा जाने लगा है कि भारत के अब सामान्य खिलाड़ियों को पैरा एथलीटों से प्रेरणा लेने की जरूरत है, क्योंकि पिछले दिनों भारत पेरिस ओलंपिक में एक भी स्वर्ण पदक नहीं जीत सका था और उसके पदकों की संख्या भी छह थी। अब सोचने वाली बात यह है कि तमाम मुश्किलों को पार करके जब पैरा एथलीट बुलंदियों को छू सकते हैं तो हमारे सामान्य खिलाड़ियों को क्या दिक्कत है। सही मायनों में पैरा एथलीटों के इस धमाल की वजह पिछले कुछ समय में सोच में आए बदलाव का यह नतीजा है।

भारत के लिए स्वर्ण जीतने वाले नीतेश कुमार, अवनि लेखरा, सुमित अंतिल, हरविंदर सिंह, धरमवीर सिंह, प्रवीन कुमार और नवदीप सिंह में कोई भी ऐसा नहीं है, जिसने पहले अपनी शारीरिक अपंगता से उबरने के लिए संघर्ष नहीं किया हो। इन सभी ने पैरा खेलों में हाथ आजमाकर देशवासियों के सामने मिसाल पेश की है। वैसे भी युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक नायक की जरूरत होती है। पर अब देश ने इन खेलों में ढेरों नायक खड़े कर दिए हैं, इसलिए युवा भी अपनी अपंगता को दुख मनाने के बजाय खेलों में हाथ आजमाने को आगे आने लगे हैं। वह दिन भी दूर नहीं, जब भारत इन खेलों के टॉप दस देशों में नजर आ सकता है। हम पेरिस पैरालंपिक खेलों की बात करें तो भारत ने 29 में से 13 पदक एथलेटिक्स में हासिल किए हैं। भारत द्वारा जीते सात स्वर्ण पदकों में से चार और नौ रजत पदकों में से छह पदक एथलेटिक्स में आए हैं। भारत ने बैडमिंटन और निशानेबाजी में भी अच्छा प्रदर्शन किया है। पर तीरंदाजी, जूडो, टेबल टेनिस सहित कई अन्य खेलों में भी बेहतर प्रदर्शन करने की संभावनाएं हैं। भारतीय प्रदर्शन पर हम नजर डालें तो साफ दिखता है कि खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार आ रहा है। इसके लिए प्रवीण कुमार का ऊंची कूद में टोक्यो के रजत को स्वर्ण में बदलना, हरविंदर का तीरंदाजी कांस्य को स्वर्ण में बदलने के अलावा हाईजंपर शरद कुमार और निषाद कुमार, शटलर सुहास यथिराज, डिस्कस थ्रोअर योगेश का पदक का रंग बदलने को देखा जा सकता है। पैरालंपिक खेल पहले विश्व स्तर पर ही बहुत लोकप्रिय नहीं थे और भारत में तो इन खेलों की लोकप्रियता का सवाल ही कहां उठता है? यही वजह है कि भारत

शुरुआत में इन खेलों में नियमित तौर पर भाग ही नहीं लेता था। 1984 से जब इन खेलों में भाग लेना नियमित तौर पर शुरू हुआ, तब भी उसके भाग लेने में गंभीरता का एकदम से अभाव दिखता था। यही वजह है कि ज्यादातर खेलों में भाग लेने वालों की संख्या 4-6 ही हुआ करती थी। भारत ने 1984 से लेकर 2012 तक आठ खेलों में सिर्फ सात पदक ही जीते। सही मायनों में भारत में पैरा एथलीटों को सही दिशा मिलने की शुरुआत 2016 के रियो पैरालंपिक से हुई और इसमें सरकारी सहयोग के साथ देश की पैरालंपिक समिति की बागडोर पैरा एथलीटों के हाथों में आने ने अहम भूमिका निभाई। 2016 के रियो खेलों में रजत पदक जीतने वाली दीपा मलिक 2020 में इस समिति की प्रमुख बनीं तो आजकल इन खेलों की समिति के दोहरे स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया अध्यक्ष हैं। असल में यह लोग अच्छे से जानते थे कि इन खिलाड़ियों को किस तरह ट्रेनिंग की जरूरत है और उनको क्या सुविधाएं मुहैया कराई जाएं। इसी का परिणाम पहले 2020 के टोक्यो पैरालंपिक और पेरिस खेलों में देखने को मिला है। यह सही है कि 2016 में भारत ने दो स्वर्ण सहित चार ही पदक जीते। पर इन खेलों से ही भारतीय पैरा एथलीटों में यह भावना बनी कि वह भी इस स्तर पर सुर्खियां बटोर सकते हैं। यह सही है कि भारत ने 2020 के टोक्यो पैरालंपिक के 19 पदकों के मुकाबले सात स्वर्ण सहित 29 पदक जीतकर अपने प्रदर्शन को सुधारा है। वह अंक तालिका में भी 24वें से 18वें स्थान पर आकर पहली बार टॉप 20 देशों में शामिल हुआ है। पर भारतीय क्षमता का पूरा उपयोग अभी भी नहीं हो सका है। इन खेलों में भारत ने यदि एक स्वर्ण और दो रजत पदक और जीत लिए होते तो तो वह ईरान से ऊपर रहकर 14वें स्थान पर पहुंच सकता था। भारत को टॉप दस देशों में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। यह काम बहुत आसान तो नहीं पर असंभव भी नहीं है। भारत इस मुकाम तक ऐसे ही नहीं पहुंच गया है।

इसके लिए पैरालंपिक समिति ने भारत सरकार के साथ मिलकर तमाम प्रयास किए और यह इन सभी का परिणाम है। इस समिति की पूर्व अध्यक्ष दीपा मलिक कहती हैं कि मैंने इन खेलों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। इसके लिए इस खेल के आंकड़ों को इंटरनेट पर पड़वाया। प्रतिभाओं की तलाश के लिए देश में जूनियर और सब जूनियर चैंपियनशिपों का आयोजन कराया। हम सभी जानते हैं कि पैरा एथलीट किन परिस्थितियों से उभरकर सामने आते हैं, इसलिए सबसे जरूरी मनोदशा को तैयार करना होता है। आधुनिक खेलों में खिलाड़ी की प्रतिभा के साथ मनोवैज्ञानिक तैयारी का महत्त्व बहुत बढ़ गया है। भारत को ओलंपिक खेलों में प्रदर्शन सुधारना हो मानसिक मजबूती पर खासतौर से काम करने की जरूरत है।

नीति-अनीति | श्रीराम शर्मा आचार्य

महत्ता इस बात की नहीं कि सफलता कितनी बड़ी पाई गई। गरिमा इस बात की है कि उसे किस प्रकार पाया गया। अनीति का मार्ग अपनाकर कोई सफलता अधिक बड़ी मात्रा में और अधिक जल्दी पाई जा सकती है, जबकि नीति का मार्ग अपनाकर चलने से देर भी लगेगी और मात्रा भी सीमित रहेगी। अधीर व्यक्ति जल्दी और अधिक पाने की बात सोचते हैं और इसी के लिए किसी भी रास्ते कुछ भी कर गुजरने के लिए आतुर रहते हैं। सम्भव है तात्कालिक लाभ की दृष्टि से वे सफल भी रहें और बुद्धिमान भी समझे जाएं, पर अंततः यह सौदा बहुत महंगा पड़ता है। ऐसी उपलब्धियां स्वयं ही पानी के बबुले की तरह नष्ट हो जाती हैं और उस उपार्जनकर्ता को भी साथ ले डूबती हैं। इतिहास के पृष्ठों पर ऐसे अनेक नाम हैं जो आंधी तूफान की तरह उभरे और झाग की तरह तली में बैठ गए। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप, चंगेज खां, नादिरशाह, सिकंदर, हिटलर आदि के कितने नाम ऐसे हैं, जिन्हें अपने समय का सफल मनुष्य कहा जा सकता है। उनकी सफलताएं अपेक्षाकृत अधिक भी थीं, और बड़ी भी, किन्तु उनसे क्या बना? सफलताएं उन्हें महंगी पड़ीं। जो कमाया था वह चला गया, अपना भी दुखद अंत हुआ। आतंकवाद के आधार पर उपार्जित किया गया बड़प्पन देर तक न टिका, बल्कि उसका स्थान चिरस्थायी अपयश ने ले लिया। उत्पीड़ितों और शोषितों का करुण क्रंदन अनन्त काल तक उनकी आत्मा को नोंचता-कोंचता रहेगा। तस्कर डाकू और छली बात की बात में प्रचुर धन प्राप्त कर लते हैं, पर वह धन उनकी सुख-शांति में तनिक भी सहायता कर सका हो, ऐसा कभी नहीं देखा गया। एक से एक बड़ी सफलताएं पाने वाले लोग इस संसार में हो चुके हैं और होंगे। उनकी तुलना में हमारी सफलता का मूल्य तुच्छ है। ऐसी छुटपुट सफलताएं और असफलाएं तो कोई भी कभी पाता रहता है। महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सफलता किस उपाय से प्राप्त की गई? वस्तुतः वह उपाय या मार्ग ही प्रशंसा या निंदा का केंद्रबिंदु होता है। इसी के आधार पर व्यक्तित्व और कर्तृत्व की परख होती है। निंदा और प्रशंसा की पृष्ठभूमि वह प्रक्रिया ही है, जिसे सफलता की मंजिल पर चलते हुए अपनाया गया।

रीडर्स मेल

बदलना होगा नियम-कायदा

देश के एक वर्ग को उम्मीद थी कि देश की वित्त मंत्री इंश्योरेंस सेक्टर में जीएसटी दरों में कमी करके राहत प्रदान करेगी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सबसे पहले वित्त मंत्री को पत्र लिख कर ये मांग की थी। बाद में देश के विपक्ष ने भी इसी मांग को दोहराया। चिकित्सा क्षेत्र में देश के एक बड़े गरीब वर्ग के लिए आयुष्मान भारत योजना लाकर उन्हें राहत प्रदान की गई। ये योजना अखिल भारतीय स्तर पर लागू नहीं है। राज्यों में गैर भाजपा सरकारें इस योजना को लागू नहीं करती। मेडिक्लेम पालिसी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है। एक तो मेडिक्लेम के प्रीमियम इतने महंगे हो गए हैं ऊपर से जीएसटी की मार। आखिर आम आदमी खुद को कैसे अस्पतालों के भारी-भरकम खर्च से महफूज रखे। होना तो ये चाहिए कि जीएसटी में राहत के साथ-साथ सीनियर सिटीजन को प्रीमियम में भी पचास फीसद राहत मिलनी चाहिए क्योंकि अधिकतर बीमारियां इसी उम्र में ही आकर घेरती हैं। नमकीन पर जीएसटी की दरें इसलिए घटा दी गईं हैं क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग शराब और चाय के साथ इसका सेवन करता है। वाह मोदी सरकार।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

जिंदगी अनमोल है

भारत एक युवा राष्ट्र है। अर्थात यहां युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन यह दुख की बात है कि इस आबादी का बड़ा हिस्सा निराशा और अवसाद से ग्रस्त है। वह दिशाहीन और लक्ष्यहीन है, खुद को हारा हुआ महसूस करता है। लक्ष्य को हासिल करने के पागलपन में उसके अंदर संयम, संतुष्टि और सहन करने की ताकत लगातार घट रही है, और किसी क्षेत्र में असफल हो जाने पर जीवन से नफरत के भाव बढ़ रहे हैं। शिक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, प्यार जैसे कई कारण हैं जो युवाओं को आत्महत्या के लिए उकसाते हैं। 10 सितम्बर को विश्व भर में 'आत्महत्या रोकथाम दिवस' मनाया जाता है, इस दिन लोगों को आत्महत्या न करने के लिए प्रति जागरूक किया जाता है, लेकिन सामाजिक संगठनों और सरकार के प्रयासों के बावजूद देश में आत्महत्या के आंकड़ो में कमी नहीं आ रही है। युवाओं को स्वयं समझना होगा कि यह जिंदगी अनमोल है, इसे व्यर्थ ही ना गवाएं।

संदीप कुमार, मधुपुर, झारखंड

तैयार रहें सरकारी अस्पताल

पत्र 'एहतियात है जरूरी' से संबंधित है। समूचे संसार ने कोरोना में मौत का तांडव और भयावह स्थिति देखी है। इसलिए किसी भी संक्रमण को हलके में लेने की गलती कोई भी नहीं करना चाहता है। विशेषकर जब हमें मालूम है की मंकीपॉक्स ने समूचे अफ्रीका महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया था कुछ महीनों पहले। यह उस राज्य सरकार का सही कदम है जहां एक मंकीपॉक्स का मामला पाया गया है। मरीज की पहचान गुप्त रखी गई है। कोरोना महामारी से सबसे बड़ी सीख हमने यह ली है कि अपने आसपास सफाई रखने, संक्रमित लोगों से एक निश्चित दूरी बनाये रखने की आदत अपना ली है। उसी तरह हमें समाज में अपने आसपास सफाई बनाए रखनी है और जो लोग पशुओं के संपर्क में आते हैं उन्हें थोड़ी ज्यादा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है, परंतु बेहद आवश्यक यह है कि सरकारी अस्पतालों को हर तरह की स्थिति से निबटने के लिए तैयार रहना होगा।

बाल गोविंद, नोएडा

letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

राष्ट्रीय सहारा
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन द्वारा हिन्दुस्तान मीडिया वेन्चर्स लिमिटेड प्रेस, मौजा-दरियापुर, पुलिस स्टेशन-शाहपुर, दानापुर, पटना से मुद्रित तथा चतुर्थ तल, सहारा इण्डिया बिहार, बोरिंग रोड क्रासिंग, पटना से प्रकाशित। । समूह संपादक - डॉ. विजय राय। स्थानीय संपादक - संजय त्रिपाठी *।
पटना कार्यालय- 3911448/417/454/422, फैक्स : 2535935,2520760 विज्ञापन-3911455/434, प्रसार- 3911451/428